● वर्ष-4
● अंक-149
रायपुर, शनिवार
01 फरवरी 2025
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6» सर्दियों में स्किन का ख्याल...

आर्थिक सर्वेक्षण

6.3-6.8% रह सकती है वृद्धि दर

सीतारमण ने संसद में पेश किया इकोनॉमिक सर्वे

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा और राज्यसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश किया। सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, विकास के उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए, वित्त वर्ष 2026 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.3 से 6.8 प्रतिशत के बीच रहने की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश किया। आर्थिक सर्वेक्षण एक वार्षिक दस्तावेज है जिसे सरकार द्वारा केंद्रीय बजट से पहले अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

यह दस्तावेज अर्थव्यवस्था की अल्पावधि से मध्यम अवधि की संभावनाओं को सामने लाता है। आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखरेख में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग की ओर से तैयार किया जाता है। पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में अस्तित्व में आया था, जब यह बजट दस्तावेजों का हिस्सा हुआ करता था।1960 के दशक में इसे केन्द्रीय बजट से अलग कर दिया गया और बजट प्रस्तुत होने से एक दिन पहले इसे पेश किया गया। वित्त मंत्री शनिवार को वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश करेंगी।

सार्थक बाजार सुधार के प्रति किया आगाह

शुक्रवार को जारी आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया कि शेयर बाजार में मूल्यांकन बढ़ने के बावजूद भारत को

सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका के बाजारों में अगर कोई सुधार होता है, तो उसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। खासकर, कोविड-19 के बाद भारत में युवा निवेशकों की संख्या बढ़ी है, जो शेयर बाजार में सक्रिय हो गए हैं। आखिरी कुछ वर्षों पर नजर डाले तो भारत में खुदरा निवेशकों की भागीदारी खासकर युवा निवेशकों की बढ़ी है। 2020 में जहां निवेशक 4.9 करोड़ थे, वहीं 31 दिसंबर 2024 तक यह संख्या बढ़कर 13.2 करोड़ हो गई। सर्वेक्षण में यह भी कहा गया है कि अमेरिकी बाजार में जो आशावादी भावना है और वहां के बढ़े हुए मूल्यांकन, 2025 में एक बड़ा सुधार ला सकते हैं। अगर ऐसा हुआ, तो यह भारत में युवा और नए निवेशकों पर ज्यादा प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि इनमें से ज्यादातर ने पहले कभी बड़े बाजार सुधार नहीं देखे हैं।

आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अहम बिंदु

- भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.3 से 6.8 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान
- मजबूत बाह्य खाता और स्थिर निजी खपत के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत
- ऊंचे सार्वजनिक व्यय और बेहतर होती कारोबारी उम्मीदों से निवेश गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद
- वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की आर्थिक संभावनाएं संतुलित हैं।
- राजनीतिक और व्यापार अनिश्चितताएं वृद्धि के मार्ग की प्रमुख बाधाएं
- चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में खाद्य मुद्रास्फीति के नरम पड़ने की संभावना
- सब्जियों की कीमतों में गिरावट, खरीफ फसलों की आवक से मिलेगी मदद
- वित्त वर्ष 2025-26 में जिंस की ऊंची कीमतों से मुद्रास्फीति का जोखिम सीमित लगता है, भू-राजनीतिक दबाव अब भी जोखिम उत्पन्न कर रहा है
- भारत को जमीनी स्तर के संरचनात्मक सुधारों, नियमन को शिथिल करते हुए अपनी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बेहतर करने की जरूरत
- एआई के लिए उचित शासन ढांचे की कमी से प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग होने की आशंका।

साल दर साल टूटा धान खरीदी का रिकार्ड

खरीदी का आज अंतिम दिन, देर रात तक खरीदी

धान खरीदी के एवज में किसानों को 31 हजार 089 करोड़ रूपए का भुगतान

प्रदेश में रिकार्ड 149 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की हुई खरीदी

रायपुर । छत्तीसगढ़ में इस खरीफ सीजन में भी धान की रिकार्ड खरीदी हुई है। धान खरीदी के अंतिम दिन आज शाम 6.45 बजे तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 149 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी हो चुकी है। राज्य के 25 लाख 49 हजार पंजीकृत किसानों ने अब तक धान बेचा है। धान खरीदी के एवज में किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत 31 हजार 89 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी।

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि धान खरीदी के साथ-साथ कस्टम मीलिंग के लिए तेजी से साथ धान का उठाव किया जा रहा है। अभी तक 121 लाख मीट्रिक टन धान के उठाव के लिए डीओ और टीओ जारी कर दिया गया है। जिसके विरूद्ध 100 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव होचुका है।

गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा इस खरीफ वर्ष के लिए 27.78 लाख किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। इसमें 1.59 लाख नए किसान शामिल है।

सौजन्य भेंट

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका से आज राजभवन में छत्तीसगढ़ की पूर्व राज्यपाल एवं वर्तमान में उत्तरप्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल ने सौजन्य भेंट की। श्रीमती आनंदी बेन पटेल अभी छत्तीसगढ़ प्रवास पर है।

साफ हो गई रायपुर की हवा, टॉप 10 शहरों में बनाई जगह

रायपुर। भारत सरकार के वन,पर्यावरण और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण -2024 के परिणाम आज घोषित कर दिए गए हैं। इस सर्वेक्षण में रायपुर ने टॉप -10 शहरों में अपनी जगह बनाते हुए 10 लाख से अधिक आबादी वाले 41 शहरों की स्पर्धा में आठवां स्थान अर्जित किया है।

केंद्र सरकार द्वारा धूल मुक्त वातावरण , कचरे को जलाने की प्रवृति पर अंकुश , निर्माण व विध्वंस अवशेष के निपटान ,वायु गुणवत्ता स्तर और जागरूकता गतिविधियों के प्रभावी संचालन जैसे कई मापदंडों के आधार पर यह सर्वेक्षण किया गया।

नगर निगम रायपुर के कमिश्नर

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024

अबिनाश मिश्रा के अनुसार स्वच्छ वायु गुणवत्ता सुनिश्चित करने कलेक्टर एवं निगम प्रशासक डॉ गौरव कुमार सिंह के निर्देश पर अंतर विभागीय समन्वय के आधार पर बीरगांव और रायपुर नगर निगम , पर्यावरण सरक्षण मंडल , सी एस आई डी सी , परिवहन , यातायात और पुलिस विभाग मिलकर काम कर रहे हैं।

धूल कम करने निरंतर जल छिड़काव , बीटी व सीसी सड़क निर्माण , एंड टू एंड पेविंग, सी एंड डी प्रोसेसिंग प्लांट से

निर्माण व विध्वंस अवशेष को पुनः उपयोगी बनाने के साथ ही अधिकाधिक वृक्षारोपण सही कई नवाचारों पर इस बार फोकस किया जा रहा है द्य इसके अलावा यांत्रिक विधि से रात्रिकालीन सड़क सफाई का दायरा 152 किमी तक बढ़ाया गया है द्य प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की जाँच शुरू की गई है द्य जागरूकता कार्यक्रमों हेतु रणनीति आधारित आई ई सी गतिविधियां भी संचालित की जा रही हैं द्य उन्होंने कहा कि इन सभी प्रयासों का लाभ इस सर्वेक्षण में रायपुर को मिला है द्य

इस रैंकिंग में टॉप-10 शहरों में सूरत , जबलपुर , आगरा, लखनऊ , कानपुर , वडोदरा ,इंदौर ,भोपाल ,विजयवाड़ा ,अहमदाबाद और दिल्ली के नाम शामिल हैंद्य वायु गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों के प्रति लोगों को जागरूक करने , प्रदूषण के दुष्प्रभावों से सभी को सचेत करने ,वायु गुणवत्ता का तुलनात्मक अध्ययन करने व सभी के लिए स्वच्छ वायु का लक्ष्य हासिल करने भारत सरकार यह सर्वेक्षण करता है।

प्रमुख समाचार

तकरार वाली नहीं, तालमेल वाली सरकार चाहिए: मोदी

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली चुनाव को लेकर द्वारका में एक जनसभा को संबोधित किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिल्ली में मतदान होने में अब बस पांच दिन बचे हैं। दिल्ली ने ठान लिया है कि,क्कदा वालों को भगाना है, इस बार भारी बहुमत से भाजपा सरकार बनाना है। उन्होंने कहा कि भाजपा दिल्ली को जितना आधुनिक बनाना चाहती है, उसकी एक झलक यहां द्वारका में दिखती है। केंद्र सरकार ने यहां भव्य यशोभूमि का निर्माण करवाया, यशोभूमि की वजह से यहां द्वारका, दिल्ली के हजारों नौजवानों को रोजगार मिला है, यहां लोगों का व्यापार बढ़ा है। आने वाले समय में ये पूरा क्षेत्र एक प्रकार से स्मार्ट शहर होगा।मोदी ने कहा कि दिल्ली को केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन वाली सरकार चाहिए। आपने पहले कितने ही साल कांग्रेस को देखा, फिर दिल्ली पर,क्कदा वालों ने कब्जा कर लिया। आपने मुझे देश की सेवा करने का बार-बार अवसर दिया है, अब आप मुझे डबल इंजन सरकार बनाकर दिल्ली की भी सेवा करने का मौका दें। उन्होंने कहा कि बीते 11 साल में,क्कदा ने सबके साथ लड़ाई-झगड़ा ही किया है।

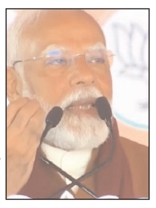

दिल्ली में बदलाव के लिए जनता तैयार: सम्राट चौधरी

नईदिल्ली। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि इस बार दिल्ली में भाजपा के पक्ष में लहर चल रही है इसलिए निश्चित पराजय की आहट से बौखलाए अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर लगातार अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। भाजपा के स्टार प्रचारक चौधरी ने तीन दिन में दिल्ली विधानसभा के संगम विहार, चांदनी चौक सहित 7 क्षेत्रों में विशाल चुनाव सभाओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि जनता बदलाव के लिए तैयार है। लहर भाजपा के पक्ष में है। आप आदमी पार्टी की सरकार के भ्रष्टाचार और झूठे वादों से परेशान लोग अबकी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर भरोसा कर रहे हैं इसीलिए इस बार यहां भी पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। चांदनी चौक में भाजपा प्रत्याशी सतीश जैन, बाडली में दीपक चौधरी और बुराड़ी में संजय तिवारी के पक्ष में चुनाव सभा को संबोधित किया। संगम विधान सभा सीट से भाजपा प्रत्याशी चंदन कुमार चौधरी, रिठाला सीट से प्रत्याशी कुलवंत राणा, सुल्तानपुर माजरा सीट से प्रत्याशी करमवीर कर्मा तथा किराड़ी के प्रत्याशी बजरंग शुक्ला के पक्ष में प्रचार किया था।

ममता कुलकर्णी को लेकर किन्नर अखाड़े में रार

नईदिल्ली। किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास ने शुक्रवार को जारी एक प्रेस बयान में घोषणा की कि उन्होंने पूर्व बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को अखाड़े से निष्कासित कर दिया है। ऋषि अजय दास ने महामंडलेश्वर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी को भी किन्नर अखाड़े से निष्कासित कर दिया जिन्होंने कुलकर्णी को ऋषि दास की जानकारी के बिना महामंडलेश्वर नियुक्त किया था। ऋषि अजय दास ने कहा कि मैंने 13 अक्टूबर 2015 को उज्जैन (एमपी) में अपने आश्रम में किन्नर अखाड़े की स्थापना की। 2016 में उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ में मेरे नाम पर जमीन आवंटित की गई थी। मैंने किन्नर अखाड़े की स्थापना की और उसका गठन किया। ऋषि अजय दास ने आगे कहा कि अखाड़े का संचालन आचार्य महामंडलेश्वर कर रहे थे। यह उस धर्म और कर्म की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा जिसके लिए मैंने इसे स्थापित किया था। वह ठीक था। लेकिन ममता कुलकर्णी जैसी शख्सियत, जिनके खिलाफ देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है, उन्हें अचानक यहां लाया गया और बिना संन्यास के सीधे महामंडलेश्वर पद पर उनका अभिषेक कर दिया गया।

डल्लेवाल की तरह करूंगा आंदोलन: अनिल विज

नईदिल्ली। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब से वह सीएम बने हैं तब से वह अपने उड़न खटोला में यात्रा कर रहे हैं। विज ने अंबाला छावनी में जारी एक बयान में कहा कि जब से सैनी ने मुख्यमंत्री का पद संभाला है, वह अपने उड़न खटोला में यात्रा कर रहे हैं और नीचे नहीं आते। उन्होंने दावा किया कि सभी विधायक, सांसद और मंत्री यह कह रहे हैं। विज ने दावा किया कि पार्टी के एक बड़े नेता ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में उनकी हार सुनिश्चित करने की कोशिश की थी। उन्होंने यहां तक दावा किया कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई। उन्होंने विधानसभा चुनाव में उनके खिलाफ काम करने वाले अधिकारियों को स्थानांतरित करने के लिए कहा था, लेकिन 100 दिन बीत गए और कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब उन्हें पूरा विश्वास हो गया है कि इसके पीछे किसी बड़े नेता का हाथ है। गुरुवार को विज ने जनता के काम करवाने के लिए किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तरह अनिश्चितकालीन अनशन शुरू करने की चेतावनी दी थी।

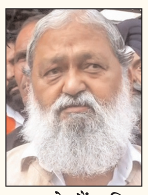

ईडी मेरी छवि खराब कर रही है : सिद्धारमैया

नईदिल्ली। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया कि मैसूर में 14 साइटें उनकी पत्नी को अवैध रूप से आवंटित की गईं, उन्होंने इसे राजनीति से प्रेरित बताया, यहां तक कि उन्हें अपने इस्तीफे के लिए बढ़ते राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ा। जहां मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) भूमि आवंटन मामले में ईडी की जांच से विवाद खड़ा हो गया है, वहीं सिद्धारमैया ने पलटवार करते हुए जांच को राजनीति से प्रेरित बताया है। मुख्यमंत्री ने पूर्व मुडा आयुक्त नटेश के पक्ष में कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए, आरोपों को खारिज कर दिया, उनका तर्क है कि यह पूरे मामले पर लागू होता है। केंद्रीय एजेंसी जानबूझकर उनकी छवि खराब करने के लिए उन्हें निशाना बना रही है। कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, और ईडी इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहा है। लोकायुक्त पहले से ही जांच कर रहा है, और यह एक स्वतंत्र निकाय है। सिद्धारमैया ने बेटे यतींद्र ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि उनके पिता मुख्यमंत्री के रूप में अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा करेंगे।

प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी के तहत 1.18 करोड़ घरों को दी गई मंजूरी

नई दिल्ली। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में शुक्रवार को कहा गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) के लाभार्थियों को कुल 1.18 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई है। सरकार ने शहरी क्षेत्रों में स्थायी आवास उपलब्ध कराने के लिए 2015 में पीएमएवाई-यू की शुरुआत की थी। सितंबर 2024 में, अतिरिक्त एक करोड़ परिवारों की सहायता के लिए पीएमएवाई-यू 2.0 की शुरुआत की गई।

89 लाख से घरों का निर्माण पूरा

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट-पूर्व दस्तावेज में कहा गया है, 25 नवंबर, 2024 तक कुल 1.18 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 1.14 करोड़ घरों की नींव रखी जा चुकी है और 89 लाख से अधिक घरों का निर्माण पूरा हो चुका है।% वर्तमान में, 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पीएमएवाई-यू 2.0 को लागू करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें वित्त वर्ष 2025 में 6 लाख घरों के लिए मंजूरी दी गई है।

देश के 29 शहरों में मेट्रो रेल और रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम चालू

वहीं शहरी बुनियादी ढांचे पर विवरण साझा करते हुए, दस्तावेज ने आगे कहा कि भारत भर के 29 शहरों में मेट्रो रेल और रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम चालू हैं या निर्माणाधीन हैं, जिनमें से 23 शहरों में वर्तमान में 1,010 किलोमीटर चालू हैं और अतिरिक्त 980 किलोमीटर का काम चल रहा है। 5 जनवरी, 2025 तक, वित्त वर्ष 25 में 62.7 किलोमीटर चालू हो गए थे, और दैनिक सवारियों की संख्या 10.2 मिलियन तक पहुंच गई थी। इन प्रणालियों ने उत्सर्जन, समय, वाहन परिचालन लागत, दुर्घटनाओं और बुनियादी ढांचे के रखरखाव में काफी बचत की है।

500 शहरों में अटल मिशन (अमृत) योजना शुरू

500 शहरों में शहरी जल प्रबंधन में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2015 में कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत) योजना शुरू की गई थी। जिसकी वजह से, नल के पानी का कवरेज 70 प्रतिशत तक बढ़ गया है, और सीवरेज कवरेज 62 प्रतिशत तक बढ़ गया है। मिशन ने प्रतिदिन 4,649 मिलियन लीटर की जल उपचार क्षमता बनाई या बढ़ाई है और 2,439 पार्क विकसित किए हैं, जिससे 5,070 एकड़ हरित क्षेत्र जुड़ गया है। 2021 में, सभी वैधानिक कस्बों और शहरों तक कवरेज का विस्तार करने के लिए अमृत 2.0 की शुरुआत की गई, जिसमें वित्त वर्ष 22 से वित्त वर्ष 26 तक 2.77 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। इस चरण में अब तक 1.89 लाख करोड़ रुपये की 8,923 परियोजनाएं शुरू की गई हैं। अमृत 2.0 में स्वयं सहायता समूहों को सक्रिय रूप से शामिल किया गया है और नवीन तकनीकों को बढ़ावा दिया गया है।

स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 1.50 लाख करोड़ की 7,479 परियोजनाएं पूरी

13 जनवरी 2025 तक, 1.64 लाख करोड़ रुपये की 8,058 परियोजनाएं प्रस्तावित की गईं, जिनमें 2015 में शुरू किए गए स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 1.50 लाख करोड़ की 7,479 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। 6 जनवरी, 2025 तक रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण के तहत लगभग 1.38 लाख रियल एस्टेट परियोजनाएं और 95,987 रियल एस्टेट एजेंट पंजीकृत हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि देश भर में रेरा की तरफ से लगभग 1.38 लाख शिकायतों का निपटारा किया गया है।

हफ्ते में 60 घंटे से अधिक काम करने से स्वास्थ्य पर..

हफ्ते में 70-90 घंटे काम करने पर बहस के बीच, शुक्रवार को बजट-पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण में अध्ययनों का हवाला देते हुए कहा गया कि हफ्ते में 60 घंटे से अधिक काम करने से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि डेस्क पर लंबे समय तक काम करना मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और जो व्यक्ति डेस्क पर (प्रतिदिन) 12 या उससे अधिक घंटे बिताते हैं, उनका मानसिक स्वास्थ्य खराब या संघर्षपूर्ण होता है। आर्थिक सर्वेक्षण में पेगा एफ, नफ्राडी बी (2021) और डब्ल्यूएचओ/आईएलओ संयुक्त अनुमानों से रोग और चोट के कार्य-संबंधी बोझ के निष्कर्षों का हवाला देते हुए कहा गया है, जबकि काम पर बिताए गए घंटों को अनौपचारिक रूप से उत्पादकता का एक उपाय माना जाता है, पिछले अध्ययन में प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावों का दस्तावेजीकरण किया गया है। सैपियन लैब्स सेंटर फॉर ह्यूमन ब्रेन एंड माइंड की तरफ से किए गए एक अध्ययन के आंकड़ों का हवाला देते हुए, आर्थिक सर्वेक्षण ने कहा, अपने डेस्क पर लंबे समय तक बिताना मानसिक स्वास्थ्य के लिए समान रूप से हानिकारक है। जो व्यक्ति डेस्क पर 12 या उससे अधिक घंटे बिताते हैं, उनका मानसिक स्वास्थ्य खराब/संघर्षपूर्ण होता है। उनका मानसिक स्वास्थ्य स्कोर डेस्क पर दो घंटे से कम या बराबर समय बिताने वालों की तुलना में लगभग 100 अंक कम होता है।

मोहला-मानपुर के कांग्रेस अध्यक्ष मानिकपुरी ने दिया पार्टी से इस्तीफा

■ पार्टी नेतृत्व पर उपेक्षा और अपमान का लगाया आरोप

राजनांदगांव। राजनांदगांव। आदिवासी बाहुल्य मोहला-मानपुर जिले के कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल मानिकपुरी ने शुक्रवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा भेज दिया है।

स्थानीय प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने संगठन के भीतर कार्यकर्ताओं की अनदेखी और निजी हितों को महत्व दिए जाने पर सवाल उठाते आरोप लगाया कि पार्टी को मजबूत बनाने का सिर्फ कोरा दावा किया जाता है। 2019 में भी %सीएम हाउस% के नाम पर उनके साथ अन्याय किया गया। 2024 में भी वह पार्टी की अंदरूनी राजनीति के शिकार हुए और लगातार उपेक्षा से व्यथित होकर उन्होंने इस्तीफा देने का मन बनाया।

बताया जा रहा है कि मानिकपुरी को नगर पंचायत अध्यक्ष की टिकट देने में क्षेत्रीय विधायक भोलाराम साहू ने खुलकर खिलाफत की थी। पूर्व सीएम बघेल ने क्षेत्रीय विधायक की पसंद पर टिकट की घोषणा की। इससे आहत होकर मानिकपुरी ने कांग्रेस से बरसों पुराना संबंध तोड़ दिया है और अब वे निर्दलीय चुनाव लडने की तैयारी में है। ऐसे में कांग्रेस की परेशानी बढ़ सकती है। बताया जाता हैं कि 2014 से 2019 तक मानिकपुरी नगर पंचायत के अध्यक्ष रहे और वे 2009 से 2014 तक नपं के उपाध्यक्ष

रहे। साथ ही ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। बतौर जिलाध्यक्ष गत् पिछले विधानसभा में उन्होंने सांगठनिक रूप से पार्टी को मजबूत किया। नतीजतन विपरीत परिस्थितियों के बीच कांग्रेस को मोहला-मानपुर सीट से 32 हजार की भारी भरकम अंतर से जीत मिली।

बेमेतरा जिला कांग्रेस अध्यक्ष बंसी पटेल ने पार्टी को कहा अलविदा, खरगे को भेजा त्यागपत्र

बेमेतरा। निकाय व पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। बेमेतरा कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने बंसी पटेल ने पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने गुरुवार देर शाम को सीधे एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को अपना त्याग पत्र भेजा है। बंसी पटेल ने तीन पन्ने में अपनी पीड़ा को बताया है। बंसी पटेल ने इस्तीफे में कांग्रेस पार्टी पर अपनी उपेक्षा करने का आरोप लगाया है।

नगर निकाय चुनाव में बेमेतरा के पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा को समन्वयक बनाये जाने को लेकर उन्होंने पार्टी से अपनी नाराजगी जताई है। पटेल ने आरोप लगाया है कि, पीसीसी के प्रदेश महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू ने सामाजिक आधार पर उन्हें समन्वयक बनाया है। साथ ही बेमेतरा नगर पालिका अध्यक्ष सुमन गोस्वामी को प्रत्याशी बनाए जाने पर भी बंसी पटेल ने नाराजगी जताई है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा द्वारा बेमेतरा नगर पालिका में ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष के लिए नामित किया गया है, जो कि अभी-अभी 6 साल के लिए कांग्रेस से निष्कासित हुआ था, जिसने ब्लॉक कांग्रेस भवन बेमेतरा के किराए में 5 लाख 41 हजार रुपए की हेराफेरी की व ब्लॉक काग्रेस अध्यक्ष रहते हुए भारी अनियमितता कर पार्टी को आर्थिक नुकसान पहुंचाया है।

इसी तरह नगर पंचायत कुसमी में ऐसे व्यक्ति (चन्द्रप्रकाश साहू) को कांग्रेस से अध्यक्ष की टिकट दी गई है, जो दो दिन पहले तक भाजपा से टिकट का दावेदारी कर रहा था, जिसका नाम भाजपा के पेनल में दूसरे नंबर पर था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सच्चे सिपाहियों की उपेक्षा की गई है। इस पूरे मामले को देखते हुए बंसी पटेल ने इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफा के बाद पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। चुनाव के समय जिला अध्यक्ष का त्याग पत्र दिए जाने से राजनीति चर्चा भी शुरू हो गई है।

रायगढ़ जिले में भाजपा की पूनम और नारायण निर्विरोध विजयी

रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में वार्ड नं। 18 की कांग्रेस प्रत्याशी शीला साहू के द्वारा नामांकन वापस लेने से भाजपा प्रत्याशी पूनम सोलंकी निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं। इस जीत के साथ भाजपा कार्यालय में जश्न मनाया जा रहा है।

मिली जानकारी के मुताबिक वार्ड नं। 18 से भाजपा प्रत्याशी पूनम सोलंकी के खिलाफ कांग्रेस की प्रत्याशी शीला साहू ने अपने व्यक्तिगत कारणों की वजह से चुनाव होनें से पहले ही आज अपना नामांकन वापस ले लिया जिससे भाजपा प्रत्याशी पूनम सोलंकी निर्विरोध चुन ली गई हैं। इस जीत से भाजपा में जश्न का माहौल है इस दौरान रायगढ़ विधायक एवं वित्त मंत्री ओपी चौधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष अरूणधन दीवान ने भाजपा प्रत्याशी पूनम सोलंकी को भाजपा का गमछा पहनाकर उन्हें जीत की बधाई दी।

वार्ड नं। 18 से निर्विरोध निर्वाचित हुई पूनम सोलकी ने अपने वार्डवासियों को धन्यवाद करते हुए कहा कि यहां की जनता ने उन्हें और उनके पति पर भरोसा जताया जिससे अनवरत हम पांच बार निर्वाचित होते आ रहे हैं। वार्डवासी हमारे सभी कार्य की सराहना करते थे और उसी का प्रतिफल है कि आज मै निर्विरोध चुनी गई हूं। मैं हमेशा अपने

वार्डवासियों के भरोसे पर खरा उतरने का प्रयास करूंगी।

इस दौरान रायगढ़ विधायक एवं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि कांग्रेस एक डूबती नाव है। परिवारवाद के चंगुल में पड़कर उन्होंने पूरे देश के अलावा पूरी पार्टी का बेडागर्क किया है। यही कारण है कि आज डूबती नाव से लोग कूद-कूद कर भाग रहे हैं। आज रायगढ़ के वार्ड नं। 18 में भी कांग्रेस की एक प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। जिससे नेता प्रतिपक्ष रही पूनम दिबेश सोलंकी निर्विरोध पार्षद निर्वाचित हो जाएंगी।

वार्ड नं। 45 भगवानपुर की सामान्य सीट से कांग्रेस प्रत्याशी खिरीलाल सिंह ठाकुर ने भी अपना नामांकन वापस ले लिया है। जिसके कारण यहां के भाजपा प्रत्याशी नारायण पटेल भी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं।

मेयर टिकट विनय ने कितने में खरीदी : जायसवाल

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव 2025 को लेकर प्रदेश में सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी पूरी तरह से परिवारवाद और पैसों के खेल में उलझ गई है।

स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस में सिर्फ परिवारवाद और पैसा चल रहा है। कांग्रेस के वर्तमान प्रत्याशियों के खिलाफ जनता में काफी रोष चल रहा है। चिरमिरी नगर निगम से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व विधायक विनय जायसवाल ने विधानसभा चुनाव में टिकट कटने के बाद उन्होंने खुलासा कि कांग्रेस के पार्टी प्रभारी ने उनसे 7 लाख रुपये लिए। उन्होंने कांग्रेस में खरीद फरोख्त का भी आरोप लगाया।

मंत्री श्यामबिहारी ने कांग्रेस प्रत्याशी विनय जायसवाल से सवाल पूछा कि इस बार कितने पैसे देकर पार्टी में वापस आए और चिरमिरी नगर निगम की मेयर टिकट के लिए कितने पैसे दिए। इसे लेकर कांग्रेसियों में रोष है। कार्यकर्ता और पदाधिकारी खुलकर नाराजगी जता रहे हैं। कांग्रेस के ही कई नेताओं ने चुनाव का विरोध किया है। कई नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है।

मंत्री श्याम बिहारी ने एक बार फिर नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा का परचम लहराने का दावा किया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस प्रदेशभर में बड़े अंतर से चुनाव हारने जा रही है।

स्वास्थ्य मंत्री के आरोपों पर चिरमिरी नगर निगम के कांग्रेस प्रत्याशी विनय जायसवाल ने कहा कि मंत्री जी को यह तक नहीं पता कि चिरमिरी की जनता और मेरे बीच क्या रिश्ता है। मंत्री जी कुछ भी बोले वो सब दूधभात है। ये चुनाव विनय जायसवाल और यहां की जनता के बीच के रिश्ते का चुनाव है। चार साल उनके बीच परिवार के सदस्य के रूप में जो काम किया हूं, उसका चुनाव है।

भाजपा ने बालोद की इस सीट पर नहीं उतारा प्रत्याशी

बालोद। बालोद जिले में नगरीय निकाय और त्रि स्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में राजनैतिक पार्टियों ने अपने सभी उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची जारी कर दी है। भाजपा की एक लिस्ट ने सबको चौका कर रख दिया। जिला पंचायत सदस्यों के लिए जारी की गई सूची में क्षेत्र क्रमांक 14 को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया है, यहां से किसी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है। जिला बालोद जिले की राजनीति में जिला बनने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है।

जिसपर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष चंद्रप्रभा सुधाकर ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा को कोई प्रत्याशी नहीं मिल पाया है या फिर पार्टी के अंदरूनी हालत ठीक नहीं है। वहीं, भाजपा जिलाध्यक्ष चेमन देशमुख ने सभी सीटों पर जीत का दावा किया और कहा कि हम तो जीत के लिए तैयार हैं कांग्रेस की हालत खराब है कहीं प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं तो कहीं फार्म रिजेक्ट हो रहे हैं।

आपको बता दें कि जिला

पंचायत क्षेत्र क्रमांक 14 में भाजपा का पेंच बुरी तरह से फंस गया। दो दावेदारों के नाम और उनके नेता अपने-अपने प्रत्याशी के लिए अड़े रहे परिणाम यह हुआ कि भाजपा ने उस जगह से किसी को नहीं उतारा तो वहीं कांग्रेस के एक पार्षद का फार्म रिजेक्ट हो गया।

बालोद नगर पालिका के वार्ड 15 के लिए कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी धनेश्वरी ठाकुर का आवेदन निरस्त हो गया। वैध सूची में उनका नाम नहीं आया तो एसडीएम कार्यालय परिसर में ही उनकी तबीयत बिगड़ गई। इस घटना पर भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को लेकर निश्चिंत नहीं है। अभी से वो हार मान चुके हैं। अब धनेश्वरी ठाकुर निर्दलीय चुनाव में प्रत्याशी रहेंगे, वे पिछले कार्यकाल में कांग्रेस से पार्षद थे।

2 जनवरी को मिले शव के मामले में खुलासा

■ पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

गौरेला पेंड्रा मरवाही। गौरेला पेंड्रा मरवाही में पेण्ड्रा थाना के कोटमी चौकी क्षेत्र स्थित सोननदी चेक डेम के पास बीते 02 जनवरी 2025 को सलीम खान (57 वर्ष, निवासी सेवरा दुबटिया) का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारियों नेतृत्व में साइबर सेल और थाना पेंड्रा की संयुक्त टीम गठित की गई,जांच क्रम में हत्या की पुष्टि होने पर अपराध दर्ज कर मामले का खुलासा किया है साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।

पूरा मामला पेंड्रा थाना क्षेत्र के कोटमी चौकी इलाके का था जहां पर बीते दो जनवरी को सोननदी स्टॉप डेम के पास एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला,शव की शिनाख्त पेंड्रा के दुबटिया निवासी 57 वर्षीय सलीम खान के रूप में हुई। घटना स्थल के पास खून के भी कुछ निशान मिले थे पुलिस अधिकारियों ने मामले में टीम गठित कर इस हत्या के मामले को सुलझाने के निर्देश दिए। जांच के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध सेवरा दुबटिया निवासी नरेन्द्र उर्फ छोटू यादव (21 वर्ष, निवासी सेवरा दुबटिया) को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पता चला कि नरेंद्र उर्फ छोटू यादव अपने मुंहबोले चाचा आलोक कश्यप की मृत्यु का बदला लेने के लिए सलीम खान की हत्या योजनाबद्ध तरीके से कर दी थी।

आठ महीने पहले आरोपी के मुंहबोले चाचा आलोक कश्यप और मृतक सलीम खान एक साथ बिलासपुर जा रहे थे, जब रास्ते में एक अज्ञात ट्रक की टक्कर से आलोक की मौत हो गई थी। लेकिन आलोक कश्यप का मुंहबोला भतीजा नरेन्द्र इसे दुर्घटना मानने को तैयार नहीं था और सलीम को इसके लिए दोषी ठहरा रहा था और

इसी बात को लेकर आरोपी नरेंद्र उर्फ छोटू यादव ने हत्या की साजिश रची और 1 जनवरी 2025 को नरेन्द्र यादव ने न्यू ईयर पार्टी के बहाने सलीम खान को अपने ऑटो में बैठाया और कुछ अन्य युवकों के साथ पिकनिक मनाने ग्राम कुडकई के पीछे निगवा डोंगरी जंगल ले गया।

वहां पर चावल, मुर्गा और शराब का इंतजाम किया गया और सलीम को अत्यधिक मात्रा में शराब पिलाई जब सलीम ने आरोपी के चाचा के साथ हुई घटना के बारे में कोई अपराध की बात कबूल नहीं की तो बाकी दोस्तों के जाने के बाद और नशा करने के बहाने आरोपी सलीम को अकेले सोन नदी के चेक डैम के पास अपनी ऑटो में लेकर गया। नशे की हालत में नरेन्द्र ने सलीम से जबरदस्ती आलोक कश्यप की मौत का सच उगलवाने की कोशिश की जिस दौरान गुस्से में आकर आरोपी नरेंद्र ने सलीम के साथ मारपीट की और फिर उसे सोननदी चेक डेम पर 25-30 फीट गहरे खाई में धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गवाहों के बयानों के आधार पर पुलिस ने आरोपी नरेन्द्र यादव को गिरफ्तार किया। मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ में आरोपी ने जुर्म स्वीकार किया मामले में पुलिस ने घटना से जुड़े खून से सना गमछा और ऑटो रिक्शा बरामद कर लिया है। जप्त साक्ष्यों को वैज्ञानिक परीक्षण हेतु भेजा जा जा रहा है और जांच जारी है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं दिए जाने के मामले में हुई सुनवाई

बिलासपुर। आंगनवाड़ी में विशेष बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं दिए जाने के मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई। राज्य शासन की ओर से भोजन का स्तर सुधारने बजट बढ़ाने की जरूरत बताई गई। कोर्ट ने केंद्र को इस संबंध में जानकारी देने और राज्य व केंद्र सरकार को शपथपत्र देने के निर्देश दिए। अगली सुनवाई 5 मार्च 2025 को होगी। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा, जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। कोर्ट कमिश्नर की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट में आंगनबाड़ी में बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं मिलने सहित कुछ सेंटर बिजली तक की व्यवस्था उपलब्ध नहीं होने की जानकारी दी गई। इस पर कोर्ट ने नाराजगी भी जताई। भिलाई चरोदा के आंगनबाड़ी केंद्र के कुछ भवन रेलवे की जमीन पर होने के मामले में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि भारतीय रेलवे कोड के अनुसार रेलवे क्षेत्र में स्थित भूमि पर आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि राज्य सरकार अनुरोध करती है तो भूमि हस्तांतरित की जा सकती है।

जमानत याचिकाओं पर 7 दिन के भीतर देना होगा निर्णय

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अतिरिक्त रजिस्ट्रार (न्यायिक) ने राज्य के जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों, जमानत याचिकाओं और विचाराधीन प्रकरणों के त्वरित निपटारे के लिए अहम आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि जमानत याचिकाओं पर संबंधित न्यायालयों को एक सप्ताह के भीतर निर्णय देना होगा। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अनावश्यक विलंब से न केवल संबंधित पक्षों को परेशानी होती है, बल्कि न्यायालयों में मामलों की पेंडेंसी भी बढ़ती है। इसके साथ ही, विचाराधीन मामलों के निपटारे के लिए समय-सीमा तय की गई है। सत्र न्यायालयों में विचाराधीन मामलों को दो वर्षों में और मजिस्ट्रेट स्तर के मामलों को छह महीने में निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में यह भी उल्लेख है कि पुराने लंबित मामलों, अंतरिम आदेश वाले प्रकरणों और विशेष श्रेणी के मामलों को शीघ्र समाप्त करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। हाई कोर्ट ने इन दिशा-निर्देशों के माध्यम से न्याय प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बनाने की पहल की है।

महुआ से बना रहे थे अवैध शराब, आबकारी की कार्रवाई

गरियाबंद। छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकास और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चलते प्रशासन नशे के खिलाफ सख्त है। गरियाबंद जिले में आज जिला आबकारी टीम और रायपुर संभागीय उड़न दस्ता टीम ने अवैध शराब निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी, कि पैरी नदी किनारे बरेठिन कोना के जंगल में अवैध शराब बनाई जा रही हैं। जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची और जंगल से इसे जब्त किया। आबकारी विभाग के मुताबिक इसकी कुल कीमत 2 लाख 92 हजार रुपए आंकी गई है। विभाग ने कच्ची महुआ शराब को जप्त कर नष्ट किया। अवैध शराब निर्माण और धारण के मामले में आबकारी अधिनियम की धारा 34(1), (क), 34(1)(च) और 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। बता दें कि ये पूरी कार्रवाई गरियाबंद कलेक्टर दीपक अग्रवाल के दिशा-निर्देश पर जिला आबकारी अधिकारी रघुवर सिंह राठौर और मुकेश कुमार अग्रवाल के टीम के द्वारा की गई।

बिजली तार की वजह से हाथियों की मौत पर हुई सुनवाई

बिलासपुर। बिजली के तारों के कारण हाथियों की मौत के मामले में हाई कोर्ट में शुक्रवार को जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने ऊर्जा विभाग के सचिव से व्यक्तिगत शपथ पत्र में जवाब मांगा है। रायगढ़ वन प्रभाग के चुहकीमार जंगल में तीन मादा हाथियों, जिनमें एक शावक भी शामिल था, की मौत ढीले पड़े 11 केवी तार के संपर्क में आने से हो गई थी। यह खबर मीडिया में आने के बाद हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। इस पूरे मामले में शुक्रवार को चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस रविन्द्र अग्रवाल की डिवीजन बैंच में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन भारत ने इस मामले में हस्तक्षेप याचिका दाखिल करने के बाद हुई हाथी की मौत के मामले में एक किसान पर की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। वहीं कोर्ट ने अधिकारियों पर जांच कार्रवाई के बारे में भी पूछा। सुनवाई के दौरान यह तथ्य निकलकर आया कि एक याचिका में बिजली तारों की ऊंचाई को बढ़ाने का आदेश दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि 14 से बढ़ाना 20 फीट करना किस विभाग की जिम्मेदारी है?

चित्रकोट घूमने आए युवक ने जलप्रपात में लगाई छलांग

जगदलपुर। जगदलपुर से 40 किमी स्थित चित्रकोट जलप्रपात में एक युवक ने अचानक छलांग लगा दी। आसपास घूमने आए लोगों ने युवक को इस तरह से कूदने से मना भी किया, लेकिन युवक नहीं माना और छलांग लगा दी। आसपास के लोगों ने इस घटना का वीडियो बना सोशल मीडिया में शेयर किया है। दावा किया जा रहा है कि युवक ने आत्महत्या करने के लिए जलप्रपात में छलांग लगाई थी। वहीं, मामले की जानकारी चित्रकोट चौकी प्रभारी को दिया गई। मौके पर पहुंची पुलिस युवक को अपने साथ पूछताछ के लिए ले गई। बताया जा रहा है कि युवक नारायणपुर का निवासी है, और अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए आया हुआ था। अचानक से युवक बिना किसी को बताए पत्थरों के बीच पहुंच गया। घूमने आए लोगों ने रुकने के लिए काफी आवाज लगाई। लेकिन युवक ने किसी की भी बात नहीं मानी और जलप्रपात में छलांग लगा दी। युवक को पानी में कूदता देख के नदी किनारे खड़ा नाविक अपनी नाव लेकर युवक के पास पहुंचा और उसकी जान बचाई।

नक्सल संगठन को बड़ा झटका, 32 लाख के 7 ईनामी नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

कांकेर। छत्तीसगढ़ के उत्तर बस्तर में आज नक्सल संगठन के 7 सक्रीय नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। सभी नक्सलियों पर कुल 32 लाख रुपए का ईनाम घोषित था, जिनमें डीवीसीएम ममता समेत 3 नक्सलियों पर 8-8 लाख रूपये का ईनाम घोषित किया गया था। इन सभी नक्सलियों ने आज नक्सलवाद पर सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव के चलते राज्य सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर आज कांकेर डीआईजी और एसएसपी के समक्ष आत्म समर्पण किया है।

बता दें, ये सभी नक्सली उत्तर बस्तर के रावघाट, परतापुर एरिया कमेटी और गढ़चिरौली डिवीजन में सक्रिय थे और अब तक कई नक्सली घटनाओं में शामिल रह चुके हैं। इन पर कई प्रमुख नक्सली घटनाओं में

शामिल होने का आरोप था, जिनमें पुलिस-नक्सली मुठभेड़, आगजनी, और आईईडी विस्फोट जैसी घटनाएं शामिल हैं। इनमें से 3 माओवादी सदस्यों पर 8-8 लाख रुपये का ईनाम, एक सदस्य पर 5 लाख रुपये और 3 अन्य पर 1-1 लाख रुपये का ईनाम था। आत्मसमर्पण के बाद पुनर्वास नीति के तहत उन्हें प्रोत्साहन राशि के रूप में 25-25 हजार रुपये प्रदान किए गए हैं।

नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण के दौरान डीआईजी विपुल मोहन बाला (बीएसएफ सेक्टर कन्हारगांव, भानुप्रतापपुर), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप पटेल (भानुप्रतापपुर), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनेश सिन्हा (कांकेर), और अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर उपस्थित रहे।

एनआईए ने गिरफ्तार किए दो ओवर ग्राउंड नक्सली

गरियाबंद। एनआईए ने दो ओवर ग्राउंड नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी धनेश ध्रुव उर्फ गुरुजी और रामस्वरूप मरकाम ने विधानसभा चुनावों के दौरान गरियाबंद जिले के बड़े गोबरा गांव में 17 नवंबर 2023 को आईडी विस्फोट को अंजाम देने वाले नक्सलियों का सहयोग किया था।

नक्सलियों ने यह विस्फोट उस समय किया था, जब मतदान दल, सुरक्षाकर्मियों के साथ मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद बड़े गोबरा गांव से लौट रहा था। घटना में आईटीबीपी का एक हेड कांस्टेबल शहीद हुआ था।

एनआईए की जांच के अनुसार, राज्य में विधानसभा चुनावों के बहिष्कार के आतंकवादी संगठन के आह्वान के बाद सीपीआई (माओवादी) केंद्रीय समिति के सदस्य गणेश उइके और मनोज और विशेष क्षेत्रीय समिति के सदस्य सत्यम गावड़े ने हमले की योजना बनाई थी। बड़े गोबरा और छोटे गोबरा गांवों के ओजीडब्ल्यूएस के समर्थन से सीपीआई (माओवादी) के गोबरा दलम के कैडरों ने विस्फोट किया था।

शुरू में मैनपुर थाने में दर्ज मामला 22 फरवरी 2024 को एनआईए ने अपने हाथ में ले लिया था। एजेंसी ने दिसंबर 2024 में आरसी-05/2024/एनआईए-आरपीआर मामले में 10 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसमें जांच जारी है।

जवानों ने नक्सलियों के नापाक मंसूबों पर फेरा पानी, अलग-अलग जगहों से आईईडी किया बरामद

गरियाबंद। मैनपुर थाना क्षेत्र में जवानों ने नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेरते हुए अलग-अलग जगहों से आईईडी बरामद कर निष्क्रिय किया है। इस दौरान बीजीएल राउण्ड, इलेक्ट्रानिक डेटोनेटर, कैंची समेत कई नक्सल बरामद किया है।

दरअसल, ग्राम भालूडीग्गी और बेसराझर के जंगलों में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर जिला बल गरियाबंद टीम ई-30 और 65 वाहिनी सीआरपीएफ की संयुक्त टीम को रवाना किया गया था। सर्चिंग के दौरान अलग-अलग जगहों पर सुरक्षा बल बीडीएस टीम ने आईईडी को बरामद कर सुरक्षित रूप से नष्ट किया।

सुरक्षाबलों को सर्चिंग के दौरान जंगल में बीजीएल राउण्ड, इलेक्ट्रानिक डेटोनेटर, बैटरी, सोलर प्लेट, नक्सली दस्तावेज, नक्सली वर्दी, वायर, बेटरी, स्वीच, कैंची, कुल्हाड़ी जैसे अन्य समाग्री बरामद किया गया है।

संक्षिप्त समाचार

आचार्य श्री विद्यासागर की पुण्यतिथि में शामिल होंगे केंद्रीय गृहमंत्री शाह

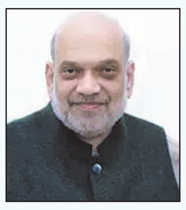

राजनांदगांव। आचार्य श्री विद्यासागर की पहली पुण्यतिथि के अवसर पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 6 फरवरी को डोंगरगढ़ आएंगे और आचार्य श्री जी के 108 चरण चिन्हों का लोकार्पण एवं प्रस्तावित समाधि का भूमिपूजन करेंगे। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल चंद्रगिरी जाएंगे। बीते वर्ष चंद्रगिरी में आचार्य ने देवलोक गमन किया था। डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी में 01 से 06 फरवरी तक आचार्य की पुण्यतिथि को प्रथम समाधि स्मृति महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। हर दिन अलग-अलग कार्यक्रम होंगे। बताया जा रहा है कि शाह ने कार्यक्रम में शामिल होने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। लिहाजा जिला प्रशासन एवं पुलिस के आला अफसर चंद्रगिरी में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। डोंगरगढ़ के चंद्रगिरी में आयोजित महामहोत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णदेव साय एक फरवरी को शामिल होंगे। मुख्यमंत्री दोपहर बाद आचार्य श्री जी की महापूजा व महाआरती में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा संबंधी अफसरों ने बैठक की है। कलेक्टर संजय अग्रवाल, आईजी दीपक झा और एसपी मोहित गर्ग ने सुरक्षा संबंधी मामलों को लेकर बैठक भी की है। डोंगरगढ़ एसडीओपी आशीष कुंजाम द्वारा भी स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर जवानों को मुस्तैद किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस स्मृति महोत्सव में देशभर से जैन समुदाय के लोग शामिल होंगे।

सीएम साय मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ जा सकते हैं प्रयागराज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने कुछ मंत्रियों के साथ विशेष विमान से कुंभ स्नान के लिए 13 फरवरी को प्रयागराज जा सकते हैं। इसकी जानकारी उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कुछ पत्रकारों के साथ चर्चा करते हुए दिए। उन्होंने बताया कि सभी मंत्रियों ने मुख्यमंत्री साय से चर्चा के बाद कुंभ स्नान का कार्यक्रम तय किया है और यह स्नान नगरीय निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद होगा।

राज्यपाल डेका से उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती पटेल ने की सौजन्य भेंट

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका से शुक्रवार को राजभवन में छत्तीसगढ़ की पूर्व राज्यपाल एवं वर्तमान में उत्तरप्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल ने सौजन्य भेंट की। श्रीमती आनंदी बेन पटेल अभी छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं।

जिस पर लगाया आरोप उसी को बना दिया कार्यकारी अध्यक्ष

रायपुर। बेमेतरा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बंशी पटेल ने पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा पर सीधे-सीधे आरोप लगाते हुए गुरुवार को ही अपना इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष खडगे को भेजा था और शुक्रवार को पीसीसी ने छाबड़ा को पटेल की जगह कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। जिले के कांग्रेसी खुद कहने लगे हैं कि चुनाव के समय में इस प्रकार की नूरा कुश्ती से पार्टी को ही नुकसान उठाना पड़ेगा। हार से कोई नहीं बचा सकता। बता दें कि पटेल ने अपने इस्तीफा में इस बात का उल्लेख किया है कि छाबड़ा ने बेमेतरा व कुसमी में ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बनवाया है जो पार्टी से निष्कासित हो चुके हैं,आर्थिक गड़बड़ी का आरोप हैं,भाजपा से जुड़े हुए हैं। पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। लेकिन पीसीसी ने पटेल को मनाने की जगह छाबड़ा को ही पुरस्कृत कर दिया। पूरे जिले में इसकी चर्चा हो रही है।

छत्तीसगढ़ से चलने वाली आठ लोकल ट्रेनें पांच फरवरी तक रहेगी रद्द

रायपुर। छत्तीसगढ़ से चलने वाली आठ

लोकल ट्रेनों को रेलवे ने रद्द कर दिया है। इससे इन ट्रेनों में रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल, आठ लोकल ट्रेनों को रद्द करने का वजह यह है कि बैकुंठ-सिलियारी सेक्शन में रिलीविंग गर्डर की डी-लॉन्चिंग के लिए ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक लिया जाएगा। इसके चलते दो से पांच फरवरी तक बिलासपुर-रायपुर के बीच चलने वाली ट्रेनों को अलग-अलग तारीख में रद्द किया गया है। 2 फरवरी को 68719 बिलासपुर-रायपुर मेमू पैसेंजर। 2 फरवरी को 68728 रायपुर-बिलासपुर मेमू पैसेंजर। 2 फरवरी को 68734 बिलासपुर-गेवरारोड मेमू पैसेंजर। 2 फरवरी को 68733 गेवरारोड- बिलासपुर मेमू पैसेंजर। 4 फरवरी को 58201 बिलासपुर-रायपुर पैसेंजर। 4 फरवरी को 58207 रायपुर-जूनागढ़ रोड पैसेंजर। 5 फरवरी को 58208 जूनागढ़- रायपुर रोड पैसेंजर। 5 फरवरी को 58204 रायपुर-कोरबा पैसेंजर।

सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति मुर्मू को बोली बेचारी

माफी मांगें अन्यथा छत्तीसगढ़ की जनता उन्हें बहुत बड़ी सजा देगी : कश्यप

रायपुर। छत्तीसगढ़ के वन और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा %बेचारी% शब्द का प्रयोग करने पर कड़ी आपत्ति जताई है और इसे कांग्रेस की महिला शक्ति के प्रति कांग्रेस की निकृष्ट सोच और आदिवासी विरोधी राजनीतिक चरित्र का परिचायक बताया है। श्री कश्यप ने कहा कि कांग्रेस में एक खानदान के लोग और उनकी चरण वंदना में लीन कांग्रेस के तमाम नेता जिस तरह की भाषा लगातार इस्तेमाल करके मातृशक्ति, जनजातीय समाज और अन्य सभी वर्गों को अपमानित कर रहे हैं, वह निंदनीय है।

कश्यप ने कहा कि सोनिया गांधी ने आज राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू के लिए बेचारी शब्द का जो उपयोग किया है, उसके लिए पूरा देश सोनिया गांधी की निंदा कर रहा है। श्री कश्यप ने कहा कि सोनिया गांधी की यह भाषा बता रही है कि कांग्रेस वैचारिक रूप से कितनी कंगाल होती जा रही है! कांग्रेस का समूचा इतिहास आदिवासी समाज के प्रति नफरत से भरा पड़ा है और यह नफरत बार-बार जाहिर होती रही है। एक आदिवासी समाज की बेटी राष्ट्रपति बनी है, यह कांग्रेस को हजम ही नहीं हो रहा है और अब तो सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू को बेचारी कहकर कांग्रेस की ओछी राजनीतिक संस्कृति का परिचय दे दिया है। श्री कश्यप ने कहा कि कोई भी आदिवासी बेचारा नहीं होता है। आदिवासियों ने इस देश की सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और हर एक प्रकार की संस्थाओं के विकास के साथ-साथ देश के 1857 के स्वाधीनता संग्राम से भी पहले से इस देश को विदेशी दासता से बचाने के लिए सशस्त्र क्रांति कर बलिदान दिया है और देश की आजादी से लेकर के अब देश के विकास में उनका महती योगदान है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस की परम्परा रही है कि वह आदिवासी समाज को हमेशा नीचा दिखाने का काम करती है। इससे पहले भी कांग्रेस के एक नेता ने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कह दिया था और कांग्रेस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। श्री कश्यप ने कहा कि श्रीमती द्रोपदी मुर्मू के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ दौरे का विरोध करके भी कांग्रेस ने अपनी विकृत मानसिकता का प्रदर्शन किया था।

प्रदेश की जनता से आदिवासी विरोधी कांग्रेस को सबक सिखाने की अपील करते हुए श्री कश्यप ने कहा कि कांग्रेस में अगर थोड़ी भी शर्म बची है, तो भूपेश बघेल, दीपक बैज समेत प्रदेश के तमाम कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की अभद्र भाषा के लिए कान पकड़कर माफी मांगें अन्यथा छत्तीसगढ़ की जनता उन्हें बहुत बड़ी सजा देगी।

निकाय चुनाव में पोस्टर वार

कांग्रेस ने लिखा- क्या हुआ तेरा वादा, वो इरादा

भाजपा ने लगाया परिवारवाद का आरोप

रायपुर। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से चुनावी सीजन में भाजपा-कांग्रेस का पोस्टर वार शुरू हो गया है। दोनों ही पार्टी एक-दूसरे के खिलाफ पोस्टर जारी कर निशान साध रहे हैं। दरअसल, चुनावी माहौल गर्म होने से दोनों ही पार्टी एक-दूसरे की कमियां गिना रही है। भाजपा ने पोस्टर जारी कर कांग्रेस पर परिवरवाद का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस ने पोस्टर में वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि क्या हुआ तेरा वादा।

प्रदेश में इन दिनों फिर से पोस्टर वार शुरू हो गया है। दोनों ही पार्टी सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल कर एक-दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। भाजपा ने एक पोस्टर जारी किया है, जिसमें प्रमोद दुबे, किरणमयी नायक, एजाज ढेबर और उनके परिजनों की तस्वीरें हैं। जिन्हें पार्टी की ओर से निकाय चुनाव में प्रत्याशी घोषित किया गया है। जिसमें भाजपा ने कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाया है। निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के साथ नाइंसाफी करती आई है। कांग्रेस परिवारवाद में लिप्त है।

दूसरी ओर कांग्रेस ने भी भाजपा के खिलाफ पोस्टर जारी किया है। जिसमें उन्होंने प्रदेश के सरकार के ऊपर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने पोस्टर जारी कर भाजपा को वादाखिलाफी का सरकार बताया है। उन्होंने लिखा है कि भाजपा के 20 में से 18 वादे अधूरे हैं। क्या हुआ तेरा वादा। वो मोदी गारंटी, वो इरादा...।

ओबीसी आरक्षण : हाईकोर्ट ने सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से मांगा जवाब

बिलासपुर। पंचायत चुनाव में ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण को लेकर दाखिल याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह याचिका ग्राम पंचायत घुटुरकुंडी, जनपद पंचायत पंडरिया, जिला कबीरधाम के निवासी हेमंत कुमार साहू ने अपने अधिवक्ताओं वैभव पी। शुक्ला और आशीष पाण्डेय के माध्यम से दायर की थी।

याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष यह मुद्दा उठाया कि पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण के निर्धारण के लिए जो संशोधित नियम बनाए गए हैं, उनमें प्रत्येक ब्लॉक में ओबीसी वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। अधिवक्ता वैभव पी। शुक्ला ने तर्क दिया कि राज्य सरकार के पास ओबीसी जनसंख्या के सही आंकड़े उपलब्ध नहीं है। ऐसे में बिना सटीक आंकड़ों के आरक्षण का आवंटन करना संविधान के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा।

इस मामले को जस्टिस बी। डी। गुरु ने गंभीरता से लेते हुए याचिका स्वीकार की और राज्य सरकार को एक सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इस मामले की सुनवाई के बाद यह स्पष्ट होगा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर पंचायत चुनावों में किस तरह का बदलाव किया जाएगा। यदि अदालत सरकार के तर्कों को अस्वीकार करती है तो आरक्षण निर्धारण प्रक्रिया में संशोधन संभव है। यह फैसला प्रदेश के पंचायत चुनावों के आरक्षण प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग की ओर से जवाब दाखिल किए जाने के बाद

छत्तीसगढ़ निकाय चुनावः राज्य निर्वाचन आयुक्त बोले-

एक ही ईवीएम में महापौर-पार्षद के लिए दो बार देना होगा वोट

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2025 के अंतर्गत मतदान पूर्व तैयारियों का जायजा लेने एक दिवसीय सरगुजा दौरे पर रहे। उन्होंने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में निर्वाचन के सम्बन्ध में जिले के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने जिले के अधिकारिओं से कहा कि स्ट्रांग रूम, मतगणना स्थल, मतदान केंद्रों में आपके द्वारा कि गई तैयारी अच्छी है। उन्होंने कहा कि ईवीएम मशीनों के सम्बन्ध में प्रचार-प्रसार की आवश्यकता है, क्योंकि इस बार एक ही मशीन में महापौर और पार्षद के लिए मतदाता को दो बार वोट देना होगा। उन्होंने मतदाताओं को ईवीएम मशीन के संबंध में अधिक से अधिक जानकारी प्रदाय कर जागरूक करने कहा । उन्होंने अधिकारियों को आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने और आचार संहिता उल्लंघन के प्रकरण को समय सीमा में त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे निर्वाचन तैयारी की सराहना की एवं नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन सुचारू एवं शांतिपूर्ण रूप से संपन्न करने आवश्यक निर्देश दिए।

राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने कहा कि महापौर, अध्यक्ष, पार्षद के लिए ईवीएम मशीन से वोटिंग होगा। मतदाताओं को ईवीएम मशीन के संबंध डेमो कर जागरूक करें। पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करने वाले निर्वाचन कार्य लगे अधिकारी-कर्मचारियों, पुलिस बल को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। संभाग आयुक्त नरेंद्र दुग्गा ने जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे निर्वाचन की तैयारी के सम्बन्ध में अवगत कराया तथा कहा कि निर्वाचन कार्य शांतिपूर्ण संपन्न होगी। वहीं पुलिस महानिरीक्षक अंकित गर्ग ने सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में जानकारी दी। कलेक्टर ने नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को सुचारू रूप संचालन एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने के सम्बन्ध में आवश्यक तैयारियों के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध करायी।

अपर कलेक्टर एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी सुनील नायक ने बैठक में निर्वाचन के सम्बन्ध में जिले की जानकारी उपलब्ध करायी। उन्होंने बताया कि नगरीय निकायों में कुल 1लाख 34 हज़ार 277 मतदाता एवं त्रिस्तरीय पंचायत में 5लाख 42 हज़ार 354 मतदाता है। नगरीय निकायों में मतदान केंद्र 173 है, जिसमें 10 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए 1099 मतदान केंद्र हैं, जिनमें से संवेदनशील 77 एवं अति संवेदनशील 12 मतदान केंद्र हैं। उन्होंने नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन सुचारू एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने के लिए आवश्यक व्यवस्था, अधिकारी कर्मचारियों की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, ईवीएम, नगरीय निकाय नामांकन की स्थिति, पंचायत निर्वाचन नामांकन की स्थिति, स्ट्रांग रूम, कमीशनिंग स्थल, मतगणना केंद्र, मतपत्र मुद्रण की व्यवस्था, निर्वाचन प्रशिक्षण कार्यक्रम, रूट चार्ट, वाहन व्यवस्था की जानकारी दी।

स्वास्थ्य सचिव कटारिया ने ली अंबेडकर अस्पताल की समीक्षा बैठक

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया ने पं. जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के बोर्ड रूम में चिकित्सा महाविद्यालय और अम्बेडकर अस्पताल की समीक्षा बैठक ली। बैठक में स्वास्थ्य सचिव ने विभिन्न आवश्यकताओं एवं भावी योजनाओं के लिए मास्टर प्लान बनाने के निर्देश दिए। बैठक के पश्चात् उन्होंने अम्बेडकर अस्पताल के रेडियोडायग्नोसिस विभाग, किचन, कैंसर विभाग, प्रस्तावित एकीकृत 700 बिस्तर अस्पताल स्थल एवं नव निर्माणाधीन मॉर्चुअरी गृह का निरीक्षण किया।

बैठक में उनके साथ आयुक्त चिकित्सा शिक्षा किरण कौशल, कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह, सीजीएमएससी की संचालक पद्मिनी भोई, चिकित्सा महाविद्यालय के डीन डॉ. विवेक चौधरी एवं अधीक्षक डॉ. संतोष सोनकर भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य सचिव एवं आयुक्त चिकित्सा शिक्षा ने अस्पताल में उपचाररत मरीज के परिजनों के ठहरने के लिए अस्पताल परिसर में परिजन आवास बनाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कलेक्टर ने मरीज के परिजनों को निशुल्क भोजन बांटने की इच्छुक संस्थाओं के लिए परिसर में चिन्हित स्थान पर प्रस्तावित शेड निर्माण कार्य को अतिशीघ्र पूरा करने को कहा है।

बैठक में स्वास्थ्य सचिव कटारिया ने चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के उन्नयन के लिए वर्तमान में चल रहे एवं प्रस्तावित निर्माण कार्यों के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। डीन डॉ. विवेक चौधरी ने चिकित्सा महाविद्यालय का संक्षिप्त परिचय देकर विभागीय बजट एवं आय-व्यय का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया। विभिन्न विभागों में उपलब्ध सुविधाएं एवं आवश्यकताओं के बारे में स्वास्थ्य सचिव को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वन विभाग से प्राप्त शासकीय जमीन में रेसीडेंट क्वार्टर एवं छात्रावास निर्माण कार्य, चिकित्सा महाविद्यालय के 1500 सीटेड ऑडिटोरियम भवन के बाहरी भाग का सौंदर्यीकरण एवं चिकित्सालय विस्तार कार्य के अंतर्गत जी प्लस टू से जी प्लस सेवन कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण कार्य पूर्व में ही प्रस्तावित है जो लोक निर्माण विभाग के सिविल वर्क के अंतर्गत प्रारंभ होना है। इसके साथ ही उन्होंने चिकित्सा महाविद्यालय भवन में स्थापित एसी के रखरखाव कार्य, परिसर में विद्युतीकरण का कार्य, सीसीटीवी कैमरा स्थापना कार्य एवं फायर फाइटिंग इलेक्ट्रिक कार्य हेतु प्रावधानित बजट एवं कार्य के अद्यतन स्थिति की जानकारी दी। स्वास्थ्य सचिव ने बैठक में मॉर्चुअरी अपग्रेडेशन एवं विस्तार कार्य को एक निश्चित समय-सीमा के भीतर पूर्ण करने के लिए सीजीएमएससी के अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके साथ ही बहुप्रतीक्षित एल-टू ट्रामा केयर सेंटर के लिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों एवं ट्रामा निर्माण समिति को आवश्यक प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करने को कहा।

अम्बेडकर अस्पताल के अधीक्षक डॉ. संतोष सोनकर ने बैठक में आगामी चार वर्ष की कार्ययोजना प्रस्तुत करते हुए स्वास्थ्य सचिव को जानकारी दी कि चिकित्सालय के लिए गार्बेज मैनेजमेंट हेतु कार्डियोलॉजी विभाग के बगल में रास्ता बनाया जाना, एस. एन. सी. यू. एवं आई. सी. यू. से फायर एक्जिट का निर्माण करवाया जाना एवं एम. आर. डी. के रिकार्ड के लिए ई-फाइलिंग जैसी भावी योजनाएं प्रस्तावित हैं। डिजिटलाइजेशन की दिशा में नेक्स्ट जेन ई हॉस्पिटल के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में डॉ. ओंकार खण्डवाल ने स्वास्थ्य सचिव को जानकारी दी और टेली रेडियोलॉजी की सुविधा के बारे में अवगत कराया।

इस अवसर पर चिकित्सा महाविद्यालय के रेडियोडायग्नोसिस विभागाध्यक्ष डॉ. एस. बी. एस. नेताम, अस्थि रोग विभागाध्यक्ष डॉ. रविकांत दास, कैंसर विभागाध्यक्ष डॉ. मंजुला बेक आदि उपस्थित थे।

शशांक सिंह आज होंगे ऑलराउंडर प्लेयर ऑफ द ईयर अवॉर्ड से सम्मानित

रायपुर। 1 फरवरी को मुंबई में बीसीसीआई के द्वारा आयोजित होने वाले पुरस्कार समारोह में छत्तीसगढ़ के पहले क्रिकेटर शशांक सिंह को लाला अमरनाथ अवार्ड फॉर द बेस्ट आलराउंडर इन डोमेस्टिक लिमिटेड ओवर्स कम्पटीशन 2023-24 पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। शशांक को यह अवॉर्ड बीसीसीआई के घरेलू सीमित ओवर के टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जा रहा है। इसी के साथ शशांक बीसीसीआई अवॉर्ड पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले क्रिकेटर बन गए हैं।

बीसीसीआई के सीमित ओवरों के टूर्नामेंट में शशांक सिंह का वर्ष 2023-24 में प्रदर्शन शानदार रहा।

कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन निरस्त होने पर बिफरे पीसीसी चीफ दीपक बैज

■ कहा- हाई कोर्ट जाएंगे हम

रायपुर। निकाय चुनाव में प्रत्याशियों के नामांकन निरस्त होने को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज सरकार के खिलाफ हमलावर रुख अख्तियार कर लिया है। उन्होंने सरकार पर दोहरी नीति के तहत काम करने का आरोप लगाते हुए निरस्त किए गए नामांकनों के मामले में हाई कोर्ट जाने की बात कही है।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक बैज ने मीडिया से चर्चा में कहा कि धमतरी में मुख्यमंत्री के करीबी को लाभ पहुँचाने के लिए बीजेपी ने कांग्रेस के मेयर कैंडिडेट का नामांकन रद्द कराया है। यह षड्यंत्रपूर्वक किया गया है, जो पूरे प्रदेश में उजागर हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि कहीं डरा-धमका कर नामांकन वापस करा रहे हैं, तो कहीं नामांकन निरस्त कर रहे हैं।

बैज ने कहा कि सूरजपुर में सरकार यादव को ओबीसी नहीं मान रही, लेकिन बिलासपुर में विधानी को ओबीसी मान रही है। 15 साल बीजेपी की सरकार में मलकीत गैदू को भी सरकार ने ओबीसी मानने से इनकार कर दिया था। ये है सरकार की दोहरी नीति। कई जगह वार्डों में भी यही स्थिति है। सरकार चुनाव से डरी हुई है, इसलिए हर हथकंडे अपना रही है। लेकिन हम डरे नहीं है। हर परिस्थिति में हम कार्यकर्ताओं के साथ खड़े है।

दीपक बैज ने कहा कि हम हाई कोर्ट जाएँगे, और लड़ाई लड़ेंगे। सीनियर नेताओं से हमारी बात हुई है। हमने अपनी रणनीति सेफ रखी है। बीजेपी ने बहुत गंदी राजनीति की है। सरकार की नियत में खोट थी, इसलिए पहले से यह सब तय करके रखा था। हम इसके ख़िलाफ़ न्याय की लड़ाई लड़ेंगे।

वहीं बेमेतरा जिलाध्यक्ष बंसी पटेल के बाद मोहला-मानपुर में जिलाध्यक्ष के पार्टी छोड़ने पर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कुछ कमजोर ज़िलाध्यक्षों को बदलने की चर्चा थी। पार्टी के टिकट नहीं देने के चलते उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दिया है। कोई पद छोड़ना चाहता है, तो उससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता। पार्टी के पास उसके मजबूत विकल्प हैं। जहां इस्तीफ़ा दिया गया है, वहां कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं। चुनाव के लिए पार्टी पूरी मज़बूत के साथ तैयार है।

पीसीसी चीफ दीपक बैज ने राजधानी में अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान करने पर तंज कसते हुए कहा कि गिरफ़्तार हुए 90% लोग रोहिंग्या नहीं, हिंदू हैं। साय सरकार देश के अन्य हिस्से से आए हिंदुओं को रोहिंग्या बताकर चुनावी माहौल को गरम करने की कोशिश कर रही है। सरकार जिन्हें रोहिंग्या कह रही है, वे अपनी रोजी-रोटी के लिए दूसरे प्रदेश से आए हैं। ऐसे में क्या हमारे गरीब मजदूर जो कर्नाटक, गोवा, जम्मू-कश्मीर, असम में मिलेंगे क्या वो रोहिंग्या हो गए?

उन्होंने कहा कि किसी गरीब मजदूर को रोहिंग्या बताकर उनकी रोजी-रोटी बंद करना गलत है। सरकार को सूची सार्वजनिक करना चाहिए कि मजदूर कहां से काम करने आए हैं। वो कौन से जाति-धर्म से आते हैं, ये सार्वजनिक करना चाहिए। क्या 2500 में 2500 रोहिंग्या हैं? देश के अंदर रोजी-रोटी के लिए अन्य राज्य में बसने का संवैधानिक अधिकार है।

भाजपा पर लगाया सत्यनारायण शर्मा ने अफसरों पर दबाव डालने का आरोप

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण शर्मा की अगुवाई में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राज्य निर्वाचन आयोग के लिए रवाना हुए। इस दौरान शर्मा ने भाजपा पर अधिकारियों पर दबाव डालने का आरोप लगाते हुए धमतरी कलेक्टर को सरकार का गुलाम बताया।

बता दें कि गुरुवार को धमतरी में कांग्रेस महापौर प्रत्याशी का नामांकन रद्द हुआ। इस मामले को लेकर कांग्रेसी राज्य निवार्चन आयुक्त से मुलाकात कर अपनी बात रखेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण शर्मा ने कहा, भाजपा खरीद फरोख, दबाव की राजनीति कर चुनाव संपन्न कराना चाहती है। शर्मा ने महापौर प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने के मामले में कानूनी लड़ाई लड़ने की बात भी कही।

पूर्व विधायक सत्यनारायण शर्मा ने कहा, हमारे प्रत्याशी का नामांकन दबाव पूर्ण निरस्त कर दिया गया है। चुनाव में इस तरह से दबाव रहेगा तो चुनाव की जरूरत क्या है। भाजपा लोकतंत्र की हत्या कर रही है। इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करेंगे। शर्मा ने कहा, अधर्म की राजनीति बीजेपी करती है। चुनाव में निष्पक्षता जैसा कुछ नहीं है। हम कोर्ट का रास्ता भी अपनाएंगे।

बता दें कि भाजपा ने कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी विजय गोलछा को निगम का ठेकेदार बताकर आपत्ति जताई थी। इस मामले में सुनवाई के बाद रिटर्निंग अधिकारी ने कांग्रेस महापौर प्रत्याशी का नामांकन निरस्त कर दिया। इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने न्यायालय जाने की बात भी कही है।

दिल्ली के चुनावी दंगल का तीखापन

उमेश चतुर्वेदी

चुनावी राजनीति आज जिस मुकाम पर पहुंच चुकी है, उसमें दिल्ली की राजनीतिक लड़ाई तीखी नहीं होती तो ही हैरत होती। वैसे भी आज राजनीतिक दलों की कामयाबी की बुनियाद उनकी उपलब्धि या लोकहित के कदम नहीं रह गये हैं। परसेप्शन, दल विशेष की कामयाबी का आधार बन गया है। इसीलिए हर दल लोकधारणा बेहतर बनाने की दिशा में जितनी तेजी से प्रयास करता है, उतने ही तीखेपन से विरोधी दल की छवि को चोट भी पहुंचाता है। दिल्ली के चुनावी दंगल में भी यह प्रवृत्ति खूब नजर आ रही है। इसमें दो राय नहीं कि दिल्ली में दांव पर सबसे ज्यादा सत्ताधारी आम आदमी पार्टी की साख है। लगातार दो चुनावों में भारी जीत के साथ सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी के लिए इस बार कठिन चुनौती है। वर्ष 2013 से लेकर हर विधानसभा चुनाव में सत्ता में वापसी की जीतोड़ कोशिश करती रही बीजेपी इस बार ज्यादा उत्साहित है। राष्ट्रीय राजधानी की राजनीति के जानकारों का मानना है कि सत्ता में वापसी की दौड़ में बीजेपी 2013 में अपनी रणनीतिक कमजोरियों की वजह से ही पिछड़ गयी। वह एक तरह से उसके लिए बड़ी फिसलन रही। बाद के दिनों में केजरीवाल की लोकप्रियता ने ऐसी गति पकड़ी कि लगातार दो चुनावों में बीजेपी खड़ी भी नहीं हो पायी। इस जंग में सबसे ज्यादा नुकसान उस कांग्रेस का हुआ, जिसका सबसे ज्यादा दिनों तक दिल्ली की जनता ने साथ दिया। वर्ष 1998 में 47.75 प्रतिशत वोट और 52 सीटों के साथ सत्ता पर काबिज होकर तीन बार जीत का स्वाद चखने वाली कांग्रेस को 2013 में 24.6 प्रतिशत वोट और आठ सीट ही मिली। करीब दो वर्ष बाद हुए चुनाव में कांग्रेस को महज 9.7 और 2020 में 4.26 प्रतिशत वोट ही मिले। दिल्ली की चुनावी राजनीति में जितनी तेजी से कांग्रेस पिछड़ती गयी, उतनी ही तेजी से आप का ग्राफ बढ़ता गया। वर्ष 2013 में आप को 29.5 प्रतिशत वोट मिले, तो अगले चुनाव में उसे बेतहाशा समर्थन मिला। वर्ष 2015 में आप को 54.3 प्रतिशत वोट और 67 सीटें मिलीं। वर्ष 2020 के चुनावों में आप 53.57 प्रतिशत वोट हासिल करने और 62 सीटें जीतने में सफल रही। इसी बीच के दो लोकसभा चुनावों में एकतरफा जीत हासिल करने वाली बीजेपी के लिए विधानसभा चुनावों में जीत मृगमरीचिका बनी रही। पार्टी को 2013 में जहां 33 प्रतिशत वोट मिले, वहीं 2015 में 32.3 प्रतिशत वोट हासिल हुए। वर्ष 2020 में बीजेपी के वोट प्रतिशत में छह प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। उसे 38.51 प्रतिशत वोट तो मिले, लेकिन जीत उससे दूर रही। हालांकि इस बार उसे आठ सीटें मिलीं। किसी भी चुनाव में जीत के लिए नेता, नीति और नीयत की बड़ी भूमिका मानी जाती है। वर्ष 2003 के चुनावों से ही दिल्ली बीजेपी प्रभावी नेता के संकट से जूझती रही है। पिछले दो चुनावों में वह प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के ही भरोसे रही। दिल्ली के वोटरों ने केंद्रीय राजनीति के लिए प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा तो जताया, पर दिल्ली के लिए केजरीवाल उसकी उम्मीद बने रहे। पर इस बार मामला बदला नजर आ रहा है। इसका संकेत मिल रहा है आप की ओर से हो रही बयानबाजी से। वैसे केजरीवाल बार-बार बीजेपी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार का प्रश्न उछाल रहे हैं। इसके जरिये वे दरअसल बीजेपी की नेता की कमी को प्रभावी मुद्दा बनाना चाहते हैं। इसके जरिये वे खुद को दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित भी कर रहे हैं। दिल्ली की राजनीति का बड़ा संकट यह है कि वह नब्बे के दशक से पहले वाली दिल्ली के जातीय और सामुदायिक समीकरणों के लिहाज से चुनावी कदम उठाती है। पूर्वांचली मतदाताओं को रिझाने के लिए पिछली बार केजरीवाल ने 16 पूर्वांचली उम्मीदवार उतारे थे, हालांकि दिल्ली के हेल्थ सिस्टम पर बढ़ते दबाव के लिए उन्हीं लोगों को जिम्मेदार ठहराया था। इसके बावजूद उन्हें भारी जीत मिली थी। इस बार भी दिल्ली में पूर्वांचली वोटर बड़ा मुद्दा बन रहा है। यह भी सच है कि दिल्ली में बीजेपी की कामयाबी तीसरे दल की ताकत पर निर्भर करती है। वर्ष 1993 के पहले विधानसभा चुनाव में जनता दल को 12 प्रतिशत से कुछ ज्यादा वोट मिले थे, उसी कारण बीजेपी को जीत मिली थी। लेकिन अगले चुनाव में जनता दल अपने अंतर्विरोधों के चलते खत्म हो चुका था, लिहाजा बीजेपी की तत्कालीन प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस को जीत हासिल करने में आसानी रही। इस बार के चुनावों में कांग्रेस पूरा दमखम लगा रही है। वह खुद को पहले की तुलना में ज्यादा ताकतवर दिखा रही है। अगर वह ताकतवर हुई, 1993 के जनता दल की तरह बारह से पंद्रह प्रतिशत तक वोट हासिल करने में सफल हुई, तो बीजेपी की संभावनाएं बढ़ेंगी। दिल्ली में कांग्रेस के जो पारंपरिक मतदाता रहे, वे अब आप के समर्थक हैं। कांग्रेस उन्हें लुभाने की कोशिश कर रही है। इस पूरी कवायद में जीत और हार का दारोमदार सबसे अधिक कांग्रेस पर है। वह जितनी ताकतवर होगी, बीजेपी की उम्मीदों की पतंग उतनी ही ऊंची उड़ेगी।

इंडी गठबंधन में राहुल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव

अनिल पांडेय

महज आठ महीने पहले आम आदमी पार्टी (आप) और कांग्रेस ने दिल्ली में मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा था।लेकिन राजनीति में समय बहुत तेजी से बदलता है।आज इसी दिल्ली में इंडी गठबंधन का मर्सिया पढ़ा जा रहा है।लेकिन इसके लिए अगर कोई चीज जिम्मेदार है तो वह है क्षेत्रीय दलों की महत्वाकांक्षाएं और राहुल गांधी। जिनकी अपनी फंतासी दुनिया है जहां वे मोदी के खिलाफ लड़ रही सेना के सेनापति हैं। राजनीति इस तरह से स्याह और सफेद नहीं होती। राहुल गांधी के पास परिवार की विरासत है, तो आप नेता अरविंद केजरीवाल भी खुद को राहुल गांधी से कम क्यों समझें? वे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में हैं और उनकी पंजाब में भी सरकार है। इतने कम समय में किसी क्षेत्रीय नेता के इतनी उपलब्धियां हासिल कर पाने का भारतीय राजनीति में कोई और उदाहरण नहीं है।उधर, यूपीए की सरकार में 10 साल तक सुपर प्रधानमंत्री रहे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी चुनावी पराजयों का विश्व रिकार्ड बनाने के करीब हैं।जाहिर है कि ऐसे में केजरीवाल राहुल गांधी को अपना नेता क्यों मानेंगे।

यही इंडी गठबंधन का अतर्विरोध है। यहां सभी की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। हर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है। वजह यह है कि गठबंधन की नेतृत्वकर्ता यानी कांग्रेस अब इस हद तक कमजोर है कि वह सहयोगी दलों की बैसाखियों पर खड़ी है। उधर, सहयोगी दल भी जानते हैं कि उन्होंने कांग्रेस की जमीन कब्जाई है और स्वाभाविक है कि कांग्रेस अपनी जमीन वापस पाना चाहेगी। ऐसे में इंडी गठबंधन की लड़ाई वास्तव में आपसी है। क्षेत्रीय दल जिनका मुख्य मुकाबला भाजपा से है, वे हरगिज नहीं चाहते कि कांग्रेस उनके प्रभाव क्षेत्र में उन्हें चुनौती दे। हालांकि कांग्रेस को अपना वजूद बचाना है तो उसे यह करना होगा।

कांग्रेस ने शुरुआत में दिल्ली में जोर-शोर से चुनावी मैदान में यह कोशिश शुरू भी की और ऐसा लगा कि इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होने जा रहा है। लेकिन जल्द ही पार्टी ने कदम पीछे खींच लिए। कांग्रेस जानती है कि जमीन वापस पाने की कोशिश में भाजपा विरोधी वोटों में सेंध लगाना भाजपा को सत्ता में लौटने का न्योता देने जैसा है। लिहाजा राहुल, प्रियंका गांधी व मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली चुनाव से तकरीबन नदारद हैं। राहुल गांधी की दो प्रस्तावित रैलियां खराब स्वास्थ्य के आधार पर रद्द कर दी गईं। अजय माकन ने केजरीवाल को भ्रष्टाचारी साबित करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, लेकिन वे खुद ही उसमें नहीं पहुंचे। यानी साफ है कि कांग्रेस चाहती है कि केजरीवाल भले ही जीत जाएं लेकिन भाजपा नहीं जीते जो कि उसकी सबसे बड़ी विरोधी है। कांग्रेस के मजबूती से लड़ने पर दलित-मुस्लिम वोटरों में बंटवारा भाजपा के दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के सपने को पूरा कर सकता है। इसी का नतीजा है कि चुनाव दिल्ली में हैं लेकिन राहुल और खड़गे रैली मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। हालांकि केजरीवाल के कांग्रेस पर लगातार हमलावर रहने और पार्टी के दबाव में राहुल गांधी चुनाव के आखिर में उतरे और शीशमहल व शराब घोटाले को लेकर केजरीवाल पर ताना कसा। हालांकि खबरों के अनुसार राहुल चुनाव से दूरी बनाए रखने और केजरीवाल के प्रति नरमी के पक्ष में थे लेकिन अंत में उम्मीदवारों का दबाव काम आया।

हालांकि जोर-शोर से दिल्ली चुनाव में उतरने के बाद कदम पीछे खींचने वाली कांग्रेस की इस दरियादिली के बावजूद इंडी के सहयोगी दल अब राहुल गांधी को नेता मानने को तैयार नहीं दिख रहे। दरअसल ज्यादातर सहयोगी दल कांग्रेस की कमजोरियों से वाकिफ हो चुके हैं। वे देख रहे हैं कि जहां कांग्रेस का भाजपा से सीधा मुकाबला है, वहां वह टिक नहीं पा रही है। ऐसे में कांग्रेस के लिए दो ही रास्ते हैं।या तो वह उन राज्यों में जहां उसका भाजपा से सीधा मुकाबला है, वहां अपनी स्थिति मजबूत करे या फिर जिन क्षेत्रीय दलों ने राज्यों में उसकी जमीन छीनी है, उसे फिर से वापस पाने की कोशिश करे। राष्ट्रीय पार्टी होने का दावा कर कांग्रेस उत्तर प्रदेश या बिहार जैसे राज्यों में खुद के लिए हैसियत से ज्यादा सीटों की मांग करती है तो हरियाणा, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश में उन्हें एक भी सीट नहीं देना चाहती। राजनीति में कोई रियायत नहीं होती और अब लगातार पराजयों से कांग्रेस की सहयोगी दलों से सौदेबाजी की ताकत काफी कम हो गई है।

लोकसभा में 99 सीटें जीत कर ही कांग्रेस ने खुद को विजेता मान लिया लेकिन अति आत्मविश्वास में वह हरियाणा जैसा राज्य हार गई जहां उसकी जीत तय मानी जा रही थी।उसके बाद महाराष्ट्र में बेहद करारी पराजय ने रही-सही कसर पूरी कर दी।सहयोगी दल इसका ठीकरा कांग्रेस और खास तौर से राहुल गांधी पर फोड़ रहे हैं जो खुद को नरेंद्र मोदी को चुनौती देने वाला नेता के तौर पर पेश करने के फेर में अपने सहयोगियों को असहज करने वाली स्थिति में डालते रहे हैं। खास तौर से महाराष्ट्र में जहां वीर सावरकर के खिलाफ लगातार उनके बयान सहयोगी शिव सेना को असहज करते रहे। महाराष्ट्र में वीर सावरकर के प्रति खासा सम्मान है और ऐसे में राहुल की इस बयानबाजी का उल्टा असर देखने को मिला।पराजयों का नतीजा ये है कि अब इंडी के सहयोगी दल भाजपा की ओर देख रहे हैं।महाराष्ट्र में जहां शरद पवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं के समर्पण की प्रशंसा कर रहे हैं तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना के मुखपत्र 'सामना' में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की जा रही है।

अब हाल ये है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि इंडी गठबंधन है या नहीं तो तेजस्वी के अनुसार गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक था।उमर अब्दुल्ला के अनुसार अगर यह गठबंधन लोकसभा चुनाव तक ही था तो अब इसे खत्म कर देना चाहिए। लगे हाथ वे यह भी कहते हैं कि इस गठबंधन के पास न कोई एजेंडा और न ही कोई नेता। शिव सेना (यूबीटी) के संजय राउत का कहना है कि गठबंधन का सबसे बड़ा दल होने के नाते इंडी ब्लाक को एकजुट रखना कांग्रेस की जिम्मेदारी है।अगर गठबंधन का वजूद नहीं बचा है तो कांग्रेस को इसकी घोषणा कर देनी चाहिए।जाहिर है कि इंडी के लिए एक नया नेता चुनने का वक्त आ गया है।क्षत्रपों की बात करें तो शरद पवार 84 साल के हैं तो ममता बनर्जी भी 70 साल से ज्यादा की हैं और हिंदी पट्टी में उनका जनाधार नगण्य है।ऐसे में देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में भाजपा को पटखनी देकर देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव विपक्षी गठबंधन के नेतृत्व के लिए एक स्वाभाविक दावेदार हो सकते हैं।

लेकिन राहुल गांधी पर लगातार उठ रहे सवालों से लगता नहीं कि इंडी गठबंधन का वजूद बचा है।दिल्ली का विधानसभा चुनाव जैसे इंडी बनाम इंडी हो गया है, जिसमें शरद पवार की एनसीपी, उद्ध ठाकरे की शिवसेना, ममता बनर्जी और सपा के अखिलेश यादव जैसे तमाम नेता खुलकर केजरीवाल के समर्थन में पहले दिन से ही हैं। वे चुप भी रह सकते थे लेकिन उनका इस मुद्दे पर मुखर होना स्पष्ट रूप से राहुल गांधी के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव है। इंडी एलायंस के सहयोगी क्षेत्रीय दलों के लिए कांग्रेस अभी भी वह पार्टी नहीं है जो अपने दम पर इतनी सीटें ला सके जो उनके सहयोग से केंद्र में सरकार बना सके।

एकात्मता के स्वर — मथुरा

भगवान् श्रीकृष्णजी की जन्मस्थली मथुरापुरी की गिनती सप्तपुरियों में की जाती है। पूर्वकाल में यहाँ पर मधु दैत्य निवास करता था। भगवान् शिव की तपस्या से उसने एक दिव्य शूल प्राप्त कर लिया था। वह शूल जब तक उसके पास रहेगा तब तक कोई उसे मार न सकेगा। उस दैत्य ने अपने निवास के लिये मधुवन बनाया। तेजस्वी मधु ने रावण की मौसेरी बहिन कुंभनिसी का अपहरण कर ब्याह किया। जिससे प्रतापी लवण नामक पुत्र पैदा हुआ। मधु नामक दैत्य के बसाने के कारण इस नगर का नाम मधुपुरी पडा। उसी को आगे चलकर मधुरा कहा गया और अब उसे ही मथुरा कहते हैं। मधु की पुत्री मधुवती का विवाह अयोध्या के राजा हर्यश्व के साथ हुआ। बडे भाई द्वारा राज्य से निष्कासित कर देने के बाद मधु ने अपना विशाल राज्य जिसकी सीमाएँ अरबसागर तक थीं, हर्यश्व को दे दिया और अपने पुत्र लवण को उसका सहयोगी बना दिया। हर्यश्व का ही पुत्र यदु हुआ जिसके वंशज यादव कहलाये। त्रेतायुग में सिंहासनासीन भगवान् श्रीराम से ऋषि-मुनियों ने कहा कि मधुपुरी में मधु दैत्य का तेजस्वी और अतिदुष्ट पुत्र लवणासुर जिसने अनुष्ठान द्वारा विशेष अस्त्र व वरदान भगवान् शिव से प्राप्त कर लिया है। वह जगत के प्राणियों पर नाना प्रकार के अत्याचार कर रहा है। वह अपनी दुष्टता से ऋषि-मुनियों, साधु-संत सभी को प्रताडित कर रहा है। उसके अत्याचार से धरा काँप उठी है। प्रभो उस दुर्दान्त दानन से हमें मुक्ति दिलाइये। आश्वासन दे ऋषि-मुनियों को विदा कर श्रीरामजी ने अपने छोटे भाई शत्रुघ्न जाके सुमिरन ते रिपु नासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकासा।। को बुलाकर आदेश दिया कि मधुपुरी के अत्याचारी लवणासुर को उसके क्रूर कर्मों का कठोर दण्ड दो। तदनुरूप शत्रुघ्न ने चतुरंगिणी सेना तैयार कर मधुपुरी पर चढ़ाई करने हेतु चलने से पूर्व जगतवंदनीय प्रभु श्रीराम से चलने की अनुमति माँगी तब प्रभु ने अपने तरकश से निकालकर एक ऐसा बाण दिया, जिसे उन्होंने रावण से युद्ध करने में भी प्रयुक्त नहीं किया था।

पुराण दिग्दर्शन .... तीसरा अध्याय

वेदों में अष्टादश पुराणों के नाम

(गतांक से आगे...)

(ख) न उस समय मृत्यु थी और नांही अमरपन था, रात और दिन की कुछ भी पहिचान न थी । माया से अविभक्त वह एक ब्रह्म ही था, उसके अतिरिक्त अन्य कुछ भीत था। (ग) अन्धकार था, और उसी अन्धकार से सब कुछ ढका हुआ सा था, यह सब नामरूपात्मक जगत् सलिल = (कार्यकारण रूप में अविभक्त था जो इस प्रकार तुच्छ - सदसद् विलक्षणता से छुपा हुवा था वही एक तपः की महिमा से प्रादुर्भूत हो गया।

वह है समाधि भाषा का एक उदाहरण, जिसमें सृष्टि के प्रादुर्भाव से पूर्वली अवस्था का वर्णन किया है। यहां शब्द और शब्दार्थ के सरल होने पर भी भावार्थ को हृदयङ्गम करना योगियों का ही काम है। जन सत् न था तो तब तद्-अभाव - असत् अवश्य होना चाहिये यही लौकिक और शास्त्रीय विवेक मान सकता है। इसीप्रकार मृत्यु की श्रविद्यमानता में निश्चय ही अमरत्व होना चाहिए, परन्तु वेद साफ शब्दों में सत् न होने पर भी असत् का और मृत्यु न होने पर भी अमरत्व का निषेध करता है। उक्त दोनों की अविद्यमानता में वह कौन सी तीरारी अबस्था थो? उसका वर्णन करना सर्वथा दुरूह हैं।

इस रहस्य का तो तुरीयावस्था में ही अनुभव हो सकता है। पुराणों में भी वेदपद्धति का अनुसरण करते हुये सैकड़ों अवाङ्-मनसोगोचर रहस्यों को समाधि-भाषा द्वारा प्रकट किया गया है, यथा- (क) इदं दृश्यं यदा नासीत्सदसदात्मकं च यत् । तदा ब्रह्ममयं तेजो व्याप्तिरूपं च सन्ततम्।। न स्थूलं न च सूक्ष्मं च शोतं नोष्णं तु पुत्रक।

क्रमशः ...

भारतीय तटरक्षक दिवस

विकास

हर साल 1 फरवरी को, भारत भारतीय तटरक्षक दिवस मनाता है, जो देश के समुद्री हितों की रक्षा करने वाले कर्मियों की वीरता, समर्पण और सेवा के लिए एक श्रद्धांजलि है। यह दिन समुद्री सुरक्षा बनाए रखने और समुद्र में आपात स्थिति का जवाब देने में तटरक्षक अधिकारियों और कर्मियों के अथक प्रयासों का सम्मान करता है। 2025 में, भारतीय तटरक्षक बल अपना 49वां स्थापना दिवस मनाएगा, जो देश की तटीय रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की लगभग आधी सदी को चिह्नित करेगा।

1 फरवरी 1977 को स्थापित, भारतीय तटरक्षक बल को समुद्री तस्करी से निपटने के लिए बनाया गया था, जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही थी। अपनी स्थापना के बाद से, तटरक्षक की

जिम्मेदारियों का विस्तार अपतटीय सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, तटीय सुरक्षा और भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) की सुरक्षा तक हो गया है। 18 अगस्त, 1978 को संसद द्वारा मान्यता प्राप्त, 1 फरवरी को आधिकारिक तौर पर भारतीय तटरक्षक (आईसीजी) दिवस के रूप में नामित किया गया था।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अनुसार, भारतीय तटरक्षक बल को दुनिया में चौथा सबसे बड़ा माना जाता है। तटरक्षक बल, भारतीय नौसेना, सीमा शुल्क विभाग और पुलिस के बीच तालमेल भारत के समुद्री सुरक्षा नेटवर्क की रीढ़ है। तटरक्षक बल विभिन्न क्षेत्रों में काम करता है, जिसमें गांधीनगर, गुजरात में उत्तर-पश्चिम क्षेत्र, चेन्नई में पूर्वी क्षेत्र और कोलकाता में उत्तर पूर्व क्षेत्र, साथ ही रणनीतिक अंडमान और निकोबार क्षेत्र शामिल हैं।

भारतीय तट रक्षक (आईसीजी) ने पिछले वर्ष दो बांग्लादेशी मछली पकड़ने वाले ट्रॉलरों को रोका और भारतीय जल क्षेत्र में अनधिकृत मछली पकड़ने में लगे 78 मछुआरों को हिरासत में लिया। यह ऑपरेशन अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (आईएमबीएल) पर नियमित गश्त के दौरान सामने आया। आईसीजी जहाज ने भारतीय समुद्री क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधि की पहचान की और तुरंत दो ट्रॉलरों को रोक लिया, जिनकी पहचान एफवी लैला-2 और एफवी मेघना-5 के रूप में की गई, दोनों बांग्लादेश में पंजीकृत हैं। निरीक्षण करने पर, जहाज अवैध मछली पकड़ने की गतिविधियों में शामिल पाए गए।

एफवी लैला-2 में चालक दल के 41 सदस्य सवार थे, जबकि एफवी मेघना-5 में 37 लोग सवार थे। आईसीजी ने आगे की जांच के लिए ट्रॉलरों को ओडिशा के पारादीप बंदरगाह तक पहुंचाया। मछुआरों और जहाजों पर भारतीय समुद्री क्षेत्र अधिनियम, 1981 के तहत मामला दर्ज किया गया। तटरक्षक बल ने एक बयान में कहा कि यह ऑपरेशन समुद्र में अनधिकृत घुसपैठ और अवैध गतिविधियों को रोकने में आईसीजी की तीव्र सतर्कता और त्वरित प्रतिक्रिया को उजागर करता है, भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और इसके जल की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

बजट से मध्यम वर्ग को उम्मीद

डॉ. जयंतीलाल

इन दिनों पूरे देश के साथ मध्यवर्ग की निगाहें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा एक फरवरी को पेश किये जाने वाले केंद्रीय बजट 2025-26 की ओर लगी हुई है। यह दिखाई दे रहा है कि देश के विकास का इंजन कहे जाने मध्यवर्ग की मुट्ठियों में धन की कमी के कारण उनके निजी उपभोग पर होने वाले खर्च में गिरावट से विकास दर प्रभावित हो रही है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि वित्त मंत्री बजट के माध्यम से टैक्स में कटौती और वित्तीय प्रोत्साहनों से आयकरदाताओं और मध्यवर्ग की क्रयशक्ति बढ़ा कर, मांग में वृद्धि कर अर्थव्यवस्था को गतिशील करने की रणनीति पर आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगी।

उम्मीद यह भी है कि वित्त मंत्री नये टैक्स रिजीम के तहत 10 लाख रुपये तक की कमाई को टैक्स फ्री कर सकती हैं। मध्यवर्ग के खर्च और निजी उपभोग का देश की विकास दर से सीधा संबंध है। कोरोना के बाद से मध्यवर्ग के पास अपने उपभोग खर्च के बाद निवेश में लगातार कमी आ रही है। जीवनशैली को बनाये रखने की लागत में तेज वृद्धि ने इस वर्ग की वित्तीय मजबूती कम की है। बढ़ती हुई खुदरा महंगाई ने भी इन पर वित्तीय दबाव बढ़ा दिया है। पिछले वर्ष में खाद्य पदार्थों की खुदरा महंगाई रिजर्व बैंक के निर्धारित मानक से अधिक रही। निजी उपभोग में कमी ने निजी पूंजीगत व्यय के चक्र की रफ्तार घटा दी है। कोविड के बाद मध्यवर्ग की कमाई में कमी आयी है। साथ ही बढ़ती वित्तीय देनदारी और कर्ज की किस्त अदायगी का बोझ भी इस वर्ग पर बढ़ा है।

बेशक कोरोना के बाद मध्यवर्ग को राहत देने की मांग लगातार तेज हुई है। विगत वर्षों में सरकार ने जहां गरीब लोगों के लिए राहतों का एलान किया, वहीं कॉरपोरेट जगत पर भी ध्यान दिया, लेकिन सबसे अधिक टैक्स देने वाला मध्यम वर्ग पीछे छूट गया। इस वर्ग पर लगाये गये टैक्स की तुलना में इन्हें सार्वजनिक सेवाओं के जरिये लाभ कम ही दिया गया। इन्हें उपयुक्त कर राहत देने से एक आर्थिक चक्र बन सकता है। ऐसे में अपेक्षा की जा रही है कि आगामी बजट सरकार के लिए लक्षित कर सुधारों को आगे बढ़ाने, शहरी उपभोग मांग बढ़ाने और मध्यम वर्ग को सीधे लाभ पहुंचाने वाली सेवाओं को बढ़ाने वाला होगा। कर राहत से मध्यम वर्ग में खपत बढ़ेगी, इससे जीएसटी संग्रह में वृद्धि होगी और कर योग्य आय वालों का आधार बढ़ेगा।

गौरतलब है कि आगामी बजट के मद्देनजर वित्त मंत्री के पास मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए कर संग्रहण संबंधी मजबूत परिदृश्य मौजूद है। पिछले 10 साल में आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या और आयकर की प्राप्ति में भारी वृद्धि हुई है। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से दिसंबर तक आयकर सहित प्रत्यक्ष कर संग्रहण करीब 16 लाख करोड़ रुपये रहा, जो कि पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 16 फीसदी से भी ज्यादा है। आगामी वित्त वर्ष के दौरान प्रत्यक्ष कर संग्रह में 12 प्रतिशत की, अप्रत्यक्ष करों में नौ फीसदी की, जीएसटी संग्रह में 10.5 प्रतिशत की और सीमा शुल्क में पांच फीसदी की वृद्धि का अनुमान है।

ऐसे में मध्यम वर्ग के लिए टैक्स में कटौती और टैक्स ढांचे को आसान बनाकर खर्च और बचत बढ़ाने की कोशिश इस बजट में दिखायी दे सकती है। वेतनभोगी वर्ग को लाभान्वित करने के विशेष प्रावधान भी नये बजट में दिखायी दे सकते हैं। नयी टैक्स रिजीम के तहत आयकर स्लैब में और बदलाव हो सकता है, ताकि अधिक से अधिक करदाता इसे अपनाने के लिए प्रेरित हो सकें। जैसे, 30 प्रतिशत की दर को 20 लाख रुपये से अधिक की आय वालों पर लागू किया जाना लाभप्रद होगा। आयकर से संबंधित पुराने टैक्स रिजीम के अंतर्गत विभिन्न टैक्स छूटों में भी वृद्धि की जा सकती है। खासकर धारा 80सी के तहत छूट बढ़ायी जा सकती है। इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन (मानक कटौती) की लिमिट भी बढ़ायी जा सकती है। अभी पुरानी व्यवस्था में नौकरीपेशा लोगों और पेंशनधारकों को 50,000 रुपये तक की छूट दी जाती है। नयी टैक्स रिजीम के तहत 75,000 रुपये की कटौती का लाभ मिलता है। मानक कटौती (स्टैंडर्ड डिडक्शन) में छूट का दायरा बढ़ाकर एक लाख रुपये किया जा सकता है।

बेशक कर सुधारों से आयकर संग्रह में आशातीत वृद्धि हुई है, पर अब भी आयकर के कर दायरे में इजाफा किये जाने की संभावनाएं हैं। वित्त मंत्री बजट में आयकर के दायरे का विस्तार करने की नयी रणनीति का एलान कर सकती हैं। बड़ी संख्या में उद्योग-कारोबार से जुड़े और कमाई करते लोग महंगी, आरामदायक और विलासिता की वस्तुओं का उपयोग करने वाले तथा पर्यटन के लिए विदेश यात्रा करने वाले लोगों में से भी बड़ी संख्या में लोग आयकर न देने का प्रयास करते हैं या फिर बहुत कम आयकर देते हैं। स्थिति यह है कि 2023-24 में 140 करोड़ से अधिक लोगों में से सिर्फ 8.09 करोड़ लोगों ने आयकर रिटर्न दाखिल किये। इनमें से भी 4.90 करोड़ लोगों ने शून्य कर योग्य आय की सूचना दी और सिर्फ 3.19 करोड़ लोगों ने ही आयकर दिया। ऐसे में देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में आयकर का योगदान बहुत कम बना हुआ है। जबकि दुनिया की कई छोटी-छोटी अर्थव्यवस्थाओं में भी आयकर का उनकी जीडीपी में बड़ा योगदान है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वित्त मंत्री बजट सत्र में नया आयकर कानून भी पेश कर सकती हैं, जो मौजूदा कानून में सिर्फ संशोधन नहीं होगा, बल्कि एक नया कानून होगा। इसके तहत अनावश्यक और अप्रचलित प्रावधानों को हटाया जायेगा, कर विवाद कम किये जायेंगे और करदाताओं के लिए अनुपालन को आसान बनाया जायेगा। इसका मकसद मौजूदा इनकम टैक्स, 1961 को आसान, स्पष्ट और समझने योग्य बनाना है। हम उम्मीद करें कि इस बार के बजट में वित्त मंत्री एक ओर छोटे आयकरदाताओं को राहत देती नजर आयेंगी, दूसरी तरफ, वह ऐसे करदाताओं को चिह्नित करते हुए भी दिखाई देंगी, जो योग्य आमदनी को छिपाते हुए या तो आयकर नहीं देते या फिर वास्तविक कमाई से कम पर आयकर देते हैं।

आज का इतिहास

1958 मिस्र और सीरिया संयुक्त अरब गणराज्य बनाने के लिए एकजुट हुए।

1960 चार अफ्रीकी अमेरिकी छात्रों ने ग्रीन्सबोरो, नॉर्थ कैरोलिना के लंच काउंटर में पहली ग्रीन्सबोरो सिट-इन का मंचन किया।

1968 कनाडा की सरकार ने रॉयल कैनेडियन नेवी, कैनेडियन आर्मी और रॉयल कैनेडियन एयर फोर्स को एक एकीकृत, कनाडाई सशस्त्र बल में विलय कर दिया।

1974 मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर को संघीय क्षेत्र घोषित किया गया।

1975 इंटरकांटिनेंटल ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन को फिलीपींस में शुरू किया गया।

1978 13 वर्षीय लड़की के यौन उत्पीड़न के आरोप में 42 दिन जेल में रहने के बाद, पोलिश फिल्म निर्देशक रोमन पोलांस्की ने जमानत छोड़ दी और संयुक्त राज्य को फ्रांस भेज दिया।

1979 अयातुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी निर्वासन से लौटे और जल्द ही ईरानी क्रांति का नेतृत्व करते हुए अमेरिका समर्थित पहलवी राजवंश को उखाड़ फेंका।

1985 एयरोफ्लोट फ्लाइट 7841 मिन्स्कनल एयरपोर्ट से टेकऑफ करने के कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें अड़सठ लोग मारे गए।

1991 अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भूकंप से करीब 1200 लोगों की मौत हुई।

1992 संयुक्त राज्य अमेरिका के तटरक्षक ने हैती से लगभग 14,000 शरणार्थियों को पहले देश को भेजा जाना शुरू किया।

2000 न्यू मैक्सिको की लॉस एलेम्स राष्ट्रीय प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों ने एड्ज़ के जीवाणुओं की उत्पत्ति का पता लगाने की घोषणा की। वैज्ञानिकों के अनुसार इन रोगाणुओं की उत्पत्ति 1930 ईसवी के आस-पास हुई।

2006 सऊदी अरब की मेना घाटी में शैतान रीति-रिवाजों की वार्षिक पत्थरबाजी के दौरान यूनाइटेड एयरलाइंस के 250 मुस्लिम तीर्थयात्रियों को कुचल दिया गया।

वक्फ कानून: सियासी हल्ले के बजाय बिल पर गंभीर विमर्श जरूरी

विराग गुप्ता

जेपीसी में बहुमत से मंजूर वक्फ के संशोधित विधेयक पर विपक्षी नेताओं और उलेमाओं की आलोचना के दो बड़े बिंदु हैं। पहला, संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) में विधायी प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ और विपक्षी सांसदों को पर्याप्त समय नहीं मिला। दिल्ली चुनाव और सियासी लाभ के लिए संसद के बजट सत्र में आपाधापी में बिल पेश करने की कोशिश हो रही है। दूसरा, इन बदलावों से मुस्लिम समुदाय के मौलिक अधिकारों का हनन होगा, जिनका संविधान के अनुच्छेद-13, 25, 26 और 29 में विशेष तौर पर जिक्र है। धर्म और सियासत के आधार पर हल्ला करने के बजाय बिल के कानूनी बिंदुओं पर गंभीर विमर्श जरूरी है।

नेहरू सरकार ने 1954 में, नरसिम्हा राव सरकार ने 1995 में और फिर मनमोहन सिंह सरकार ने 2013 में वक्फ कानून में बड़े बदलाव किए थे। इन बदलावों से वक्फ बोर्ड को मनमानी अधिकार मिलने के साथ सिविल अदालतों का क्षेत्राधिकार खत्म हो गया था। वक्फ की संपत्ति का मदरसा, कब्रिस्तान, मस्जिद, अनाथालय और इस्लामिक धर्मार्थ कार्यों में इस्तेमाल होता है। वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया ऑनलाइन डाटा पोर्टल के नवीनतम डाटा के अनुसार, वक्फ के पास 8.65 लाख संपत्तियों के तहत लगभग 9.4 लाख एकड़ जमीन है। 50 फीसदी वक्फ संपत्तियों के बारे में सही जानकारी उपलब्ध नहीं है और नौ फीसदी संपत्तियों में अवैध निर्माण से जुड़े 32 हजार मामले चल रहे हैं। वक्फ प्रशासन को पारदर्शी और कानून सम्मत बनाने के लिए 1969 में संसद में जोरदार मांग की गई थी।

कई दशक पहले राज्यसभा में बहस के दौरान विपक्ष के नेता और भाजपा सांसद सिकंदर बख्त ने कहा था कि वक्फ संपत्तियां गरीब मुसलमानों की बेवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और यतीम बच्चों की अमानत हैं, जिनमें खयानत हो रही है। जायदाद को महफूज रखने और लूटमार से बचाने के लिए पारदर्शिता, ऑडिट और कुशल प्रशासन जरूरी है। 2006 में सच्चर समिति की रिपोर्ट में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने, अभिलेखों की देखरेख और ऑडिट की सिफारिश की गई थी। 2008 में राज्यसभा में पेश संसदीय समिति की रिपोर्ट में वक्फ बोर्डों में सीईओ के तौर पर वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मुतवल्लियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के प्रावधान की सिफारिश की गई थी। बरेलवी मौलाना के अनुसार, वक्फ बोर्ड के रहनुमाओं ने भू-माफिया से मिलकर करोड़ों रुपये की जमीन बेच दी। इस बिल के आने के बाद भ्रष्टाचार कम होने के साथ मुसलमानों की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति मजबूत होगी।

संसद के कानून से जमींदारी और राजाओं का प्रिवी पर्स खत्म हो गया। पर वक्फ कानून से हासिल मनमाने अधिकारों की आड़ में वक्फ बोर्ड पुरातत्व विभाग के अधीन 120 प्राचीन स्मारकों, मंदिरों और किलों पर दावा ठोक रहे हैं। सनद रहे कि बाबरी मस्जिद मामले में वक्फ बोर्ड पक्षकार था और अब मथुरा व काशी जैसे अनेक स्थानों में चल रही मुकदमेबाजी में वक्फ का दावा है। संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची के अनुसार अनुसूचित जनजाति के लोगों की भूमि की सुरक्षा का विशेष प्रावधान है, पर उन संपत्तियों पर भी वक्फ बोर्ड के दावे हैं। कर्नाटक में वक्फ बोर्ड अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर लोगों को मैरिज सर्टिफिकेट देने लगे, जिस पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने नवंबर, 2024 में रोक लगा दी।

विवादित संपत्ति के दान और संपत्ति के लिए अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए प्रस्तावित कानून में प्रावधान हैं। उनके अनुसार, कम से कम पांच साल से इस्लाम का पालन करने वाले वैध संपत्ति के मालिक ही वक्फ बना सकते हैं। वेबसाइट पर वक्फ संपत्ति का विवरण घोषित करना अनिवार्य होगा। स्वतंत्र ऑडिट और केंद्रीय पोर्टल के माध्यम से संपत्तियों के अनिवार्य पंजीकरण के प्रावधान से वक्फ के मौखिक दावों पर लगाम के साथ मुकदमेबाजी में कमी आएगी। ये बदलाव संपत्ति पंजीकरण, स्टांप ड्यूटी और लिमिटेशन कानून के भी अनुरूप हैं। शाहबानो मामले में कट्टरपंथी ताकतों के दबाव की वजह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राजीव गांधी सरकार ने संसद से बदल दिया था। इतिहास से सबक लेते हुए यह समझने की जरूरत है कि तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति से दूसरे समुदायों में कट्टरपंथी ताकतों को बढ़ावा मिलता है। दिल्ली और दूसरे राज्यों में वक्फ बोर्ड के माध्यम से इमाम और मौलवियों को वेतन मिलता है। अब उसी तर्ज पर हिंदू पुजारियों के लिए वेतन के साथ सनातन बोर्ड के गठन की मांग हो रही है। ईसाइयों की धार्मिक संपत्तियों के लिए मद्रास हाई कोर्ट ने नियामक बनाने की बात कही है। संविधान में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है, पर मुस्लिम समुदाय अभी भी शरिया कानूनों से संचालित है। इसलिए धर्म-निरपेक्षता की आड़ में वक्फ कानून में हो रहे बदलावों का विरोध ठीक नहीं है।

हिंदू धर्म में दलित और पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए आरक्षण का प्रावधान है। नए बिल के अनुसार केंद्रीय वक्फ बोर्ड, राज्य वक्फ बोर्ड और वक्फ न्यायाधिकरणों में महिलाओं और गैर-मुस्लिमों के साथ शिया, दाऊदी बोहरा, अहमदियों, आगरवानी जैसे मुस्लिम संप्रदायों का प्रतिनिधित्व होगा। वक्फ कानूनों में बदलाव से मुस्लिम समाज के पसमांदा और ओबीसी जातियों को वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में बेहतर भूमिका के साथ आमदनी में सही हिस्सेदारी मिलेगी। इस्लामिक देशों में कई दशक पहले फैमिली वक्फ खत्म कर दिया गया था। नए बिल में फैमिली वक्फ में महिलाओं को प्रगतिशील तरीके से अधिकार दिए गए हैं। पुरानी सरकारों ने वक्फ कानून में जो बदलाव किए थे, उनके अनुसार सरकारी या गैर-मुस्लिम की संपत्ति के गलत अधिग्रहण होने पर वक्फ ट्रिब्यूनल के पास ही अपील करनी पड़ती है। नए बिल के अनुसार, कानून बनने पर अदालतों का अधिकार बहाल होगा, जो पूरी तरह से संविधान के प्रावधानों के अनुकूल है। भूमि राज्यों का विषय है, इसलिए वक्फ कानून में बदलाव से पहले सभी राज्यों के साथ पर्याप्त विमर्श होना चाहिए। विपक्षी सांसदों ने अनेक बिंदुओं पर आपत्तियां दर्ज कराई हैं। कानून पारित होने से पहले इन सभी बातों का ध्यान नहीं रखा गया, तो कानून बनने के बाद वक्फ मामला अदालतों में उलझ सकता है।

महाकुंभ : त्रासदी पर समय रहते नियंत्रण से संतोष

दीपक कुमार शर्मा

करोड़ों लोगों के आने के बावजूद अब तक बेहद शांति व कुशलता के साथ प्रबंधित हो रहे महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन मची भगदड़ के बाद के दृश्य वाकई परेशान करने वाले हैं और सवाल उठाते हैं कि देश में धार्मिक आयोजनों में ऐसे दृश्य बार-बार खुद को क्यों दोहराते हैं, जिनमें आस्था अव्यवस्था के आगे बेबस नजर आने लगती है। कुछ समय पहले हाथरस में एक सत्संग में बाबा की चरण-धूलि लेने के लिए मची भगदड़ में सौ से भी ज्यादा लोगों की जानें चली गई थीं। इसी तरह, कुछ दिनों पहले बागपत में जैन निर्वाण महोत्सव के दौरान लकड़ी की सीढ़ियां टूटने से हुए हादसे में भी कुछ ऐसा ही दिखा। गनीमत है कि कुंभ के दौरान हुआ हादसा एक सीमित क्षेत्र में हुआ और समय रहते इस पर काबू पा लिया गया, जो एक बड़ी त्रासदी भी हो सकता था। फिर भी इसने कुछ चीजों की ओर तो ध्यान दिलाया ही है। धार्मिक आयोजनों में भीड़ तो होती ही है, जिनमें प्रशासन की तैयारियां अक्सर नाकाफी ही साबित होती हैं। पिछले कुंभ में भी कुछ ऐसे ही दृश्य दिखे थे और तब भी प्रशासन को खरी-खोटी सुनाकर सबने हाथ धो लिए थे। प्रशासन को तो हमेशा ही कह सकते हैं कि उसे ध्यान देना चाहिए, जो सही भी है। लेकिन जब भी धार्मिक आयोजन होते हैं, जिसमें ज्यादा संख्या में लोग आने हों, तो भक्तों का अति उत्साह अपने आप में भीड़ के स्व-नियंत्रण का मसला भी बन जाता है। महाकुंभ जैसे इतने बड़े आयोजन पर सहज-स्वाभाविक है कि लोग स्नान करना चाहेंगे, क्योंकि यह उनके जीवन में एक अपूर्व अवसर की तरह होता है और यह बिल्कुल स्वाभाविक भी है। लेकिन यह भी समझना चाहिए कि अव्यवस्थित भीड़ और अफवाहें कई बार त्रासदी को जन्म देती हैं। अतिरिक्त उत्साह और व्यावहारिकताओं पर ध्यान दिया जाए, तो बहुत सारी चीजों को रोका जा सकता है। आस्था एक व्यक्तिगत विषय है, लेकिन जब यह सार्वजनिक रूप लेता है, तो इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, जितना प्रशासन का दायित्व है, उतना ही समाज के अंग के तौर पर हमारा भी। यह समझने की बात है कि भक्ति का अर्थ केवल श्रद्धा प्रकट करना नहीं, बल्कि दूसरों की सुरक्षा व जीवन के प्रति संवदेनशील होना भी है। सैलाब को उसकी सीमाओं के साथ भी देखना चाहिए। श्रद्धा व अनुशासन का संगम होना ही चाहिए। करोड़ों लोगों का प्रबंधन एक दुष्कर कार्य है और यह संतोष की बात है कि समय रहते इस पर नियंत्रण भी पा लिया गया, फिर भी इससे सबक जरूर लेना चाहिए, ताकि ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

30 की मौत या 30 करोड़ लोगों का सकुशल स्नान करना बड़ी बात है?

नीरज कुमार दुबे

महाकुंभ मेले में मौनी अमावस्या पर्व पर मची भगदड़ में 30 श्रद्धालुओं की मृत्यु होना बहुत दुखद खबर है। लेकिन इस हादसे के बावजूद आठ करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने उसी दिन स्नान किया और सकुशल वापस घर गये यह उत्तर प्रदेश प्रशासन की एक बड़ी उपलब्धि भी है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की आबादी देखें तो वह लगभग 60 लाख के आसपास है। कुम्भ मेले में अब तक आ चुके श्रद्धालुओं का आंकड़ा देखें तो वह 30 करोड़ के पास पहुँचने वाला है। योगी सरकार का आकलन है कि 26 फरवरी तक चलने वाले धरती के इस सबसे बड़े मेले में 45 करोड़ के आसपास लोग आयेंगे। ऐसे में आप कल्पना करके देखिये कि इतनी बड़ी भीड़ को संभालने और उनके लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं करने के लिए प्रशासन ने कितने समय से कितने प्रयास किये होंगे।

भगदड़ की एक घटना को लेकर पूरी व्यवस्था पर प्रश्न उठाने वालों को यह भी देखना चाहिए कि मौनी अमावस्या से पहले ही रात को लगभग पांच करोड़ लोग सकुशल स्नान कर चुके थे और घटना के बाद भी आठ करोड़ लोगों ने सकुशल स्नान किया था। इससे पहले के अमृत स्नान के दौरान भी लगभग पांच करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया था लेकिन किसी को खरोंच तक नहीं आई थी। जिन लोगों को एक दिन में एक जगह पर आठ से दस करोड़ लोगों का स्नान करना मामूली बात लगती है उन्हें पता होना चाहिए कि यह संख्या कई देशों की कुल जनसंख्या से भी अधिक है।

आपने देखा होगा कि भगदड़ की घटना की खबर मिलते ही विपक्ष के कई नेता इतनी तेजी से बयान जारी करने लग गये थे जैसे कि वह पहले से टाइप करके रखा गया था और किसी हादसे की प्रतीक्षा की जा रही थी ताकि योगी सरकार को घेरा जा सके। कुछ मीडिया संस्थानों ने भी सनसनी फैलाने में देरी नहीं लगाई और अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते हुए सिर्फ अव्यवस्था संबंधी खबरें चलाईं। जबकि सच्चाई यह थी कि घटना के कुछ ही मिनटों के भीतर हालात पर काबू पाया जा चुका था और इसी का परिणाम था कि पूरे दिन स्नान सुचारू रूप से चला और आज भी करोड़ों लोग अब तक डुबकी लगा चुके हैं और सरकार के इंतजामों की तारीफ कर रहे हैं।

कुछ लोगों ने सोशल मीडिया और मीडिया के मंचों से सवाल उठाया कि जब यूपी सरकार सुबह-शाम श्रद्धालुओं की संख्या के आंकड़े जारी कर रही है तो उसे सुबह मारे गये श्रद्धालुओं की संख्या बताने में सोलह घंटे क्यों लग गये? ऐसे लोगों को समझना होगा कि महाकुंभ मेले में आ रहे श्रद्धालुओं की गिनती के लिए एआई कैमरों सहित तमाम तरह की तकनीक की मदद ली जा रही है और भगदड़ में मारे गये लोगों की संख्या बताने में समय इसलिए लगा होगा क्योंकि मौत का आंकड़ा किसी की मृत्यु के बाद ही बताया जाता है। यदि आपने घटना के बाद के वीडियो देखें हों तो उसमें साफ प्रदर्शित हो रहा है कि घायल अवस्था में कई लोगों को एम्बुलेंसे ग्रीन कॉरिडोर बनाकर तेजी से अस्पताल ले जा रही हैं। यूपी सरकार सुबह से ही कह रही थी कि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हो सकता है कि किसी की इलाज के दौरान मृत्यु हुई हो या किसी की अस्पताल लाये जाने के दौरान ही मृत्यु हो गयी हो। यह भी सर्वविदित है कि जब तक डॉक्टर किसी को मृत घोषित नहीं कर देते और उसकी पहचान तथा अन्य औपचारिकताएं पूरी नहीं हो जातीं तब तक आंकड़े सामने नहीं आते। यहां यह भी ध्यान रखना चाहिए कि एक हादसा जो हो चुका था उसके बारे में उस समय ज्यादा जानकारी देने से यदि हालात बिगड़ जाते तो और भी हादसे हो सकते थे क्योंकि करोड़ों की संख्या में लोग एक जगह पर मौजूद थे।

30 श्रद्धालुओं की मौत होना हृदय विदारक है और मृतकों के परिजनों की दशा समझी जा सकती है लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि अब तक 30 करोड़ लोग सकुशल स्नान करके जा चुके हैं। देखा जाये तो कुंभ मेले की बड़ी तस्वीर भगदड़ की एक घटना की नहीं बल्कि यहां करोड़ों की संख्या में उत्साह के साथ स्नान कर बिना किसी नुकसान के जा चुके श्रद्धालुओं की है। यहां हमें यह भी समझना होगा कि भगदड़ या भूकंप या दुर्घटनाओं या हत्याओं से होने वाली मौतों पर प्रतिक्रिया करते समय या उससे संबंधित समाचार दिखाते समय हमें संयम बरतना चाहिए।

बहरहाल, निश्चित रूप से कुंभ भगदड़ बड़ी खबर है। लेकिन भारत जैसे भीड़भाड़ वाले देश में भगदड़ से होने वाली मौतें विभिन्न बीमारियों और कारणों से होने वाली कुल मौतों का केवल एक अंश मात्र हैं। अल्जाइमर दुनिया भर में मौत का सातवां प्रमुख कारण है। लेकिन इस बीमारी से होने वाली मौतें कभी भी पेज-1 की खबर नहीं बनती ना ही कोई मीडिया चैनल इस पर प्राइम टाइम में या अन्य समय पर खबर दिखाता है। भारत में सड़क दुर्घटनाओं और तमाम तरह की बीमारियों से होने वाली मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है लेकिन वह कभी बड़ी खबर इसलिए नहीं बनती क्योंकि इसमें किसी को राजनीति करने का मौका नहीं मिलता।

पाकिस्तान के लिए परेशानी न बन जाएं ट्रंप

मरिआना बाबर

अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पद संभाले अभी एक महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। दुनिया का हर मुल्क बेचैनी से इंतजार कर रहा है कि वह आगे क्या करने वाले हैं। दक्षिण एशिया के देश भी इसका अपवाद नहीं हैं। उनके आदेश पाकिस्तान समेत इस क्षेत्र के अन्य मुल्कों को भी प्रभावित कर रहे हैं।

पाकिस्तान के पूर्व विदेश और रक्षा मंत्री इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर-खान कहते हैं, %प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनकी टीम को अमेरिका का समर्थन बनाए रखने में काफी मशक्कत करनी होगी। प्रधानमंत्री को पाकिस्तानी हितों की रक्षा और प्रसार के लिए गैर-पारंपरिक व बहुआयामी कूटनीति का इस्तेमाल करना होगा, यानी अमेरिका को पाक निर्यात का सबसे बड़ा गंतव्य बनाए रखना होगा और पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिकी आर्थिक दांव को रोकना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात मौजूदा कार्यक्रम को जारी रखने के लिए आईएमएफ में आवश्यक समर्थन बनाए रखना होगा।

व्यक्तिगत रूप से, मुझे लगता है कि ट्रंप पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती बनने वाले हैं और इसी से जुड़ा सवाल है कि पाकिस्तान के चीन से कैसे संबंध रहते हैं और ट्रंप अफगानिस्तान को कैसे संभालते हैं। ट्रंप ने पदभार संभालने से पहले और बाद में भी चीन से संपर्क साधने की कोशिश की है। उन्होंने चीनी राष्ट्रपति को अपने शपथ ग्रहण समारोह में भी बुलाया था और संकेत दिए हैं कि ट्रंप के नए कार्यकाल में दोनों मुल्कों के बीच तालमेल हो सकता है। लेकिन अभी शुरुआती दिन हैं।

पाकिस्तान के लिए अच्छी बात यह होगी कि अगर चीन और अमेरिका के संबंध काफी हद तक संतुलित हो जाएं, तो चीन से उसके द्विपक्षीय रिश्तों पर कम दबाव पड़ेगा। हमने देखा है कि ट्रंप कूटनीतिक चैनलों को दरकिनार करके विश्व नेताओं से व्यक्तिगत संबंध बनाना चाहते हैं। ट्रंप और इमरान खान की पहली मुलाकात में ही अच्छी दोस्ती हो गई थी। हालांकि 2019 में उन्होंने अपने कार्यालय में इमरान खान से बातचीत के दौरान एक धमाका करते हुए कश्मीर पर इमरान खान को बेवकूफ बना दिया था।

उन्होंने इमरान खान से कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें कश्मीर मसले पर मध्यस्थता करने के लिए कहा है। इस पर खुश होते हुए इमरान खान ने कहा कि अगर वह कश्मीर के लिए कुछ कर सकें, तो लाखों लोग उनके लिए प्रार्थना करेंगे। यह वास्तव में एक कूटनीतिक झांसा था और जब भारत ने ट्रंप की टिप्पणी का खंडन किया, तब ट्रंप चुप हो गए और फिर कभी कश्मीर का जिक्र नहीं किया।

ट्रंप की नई पारी की शुरुआत में पाकिस्तान के सामने एक चुनौती ट्रंप की शरणार्थी नीति भी है, क्योंकि ट्रंप ने बाइडन युग के शरणार्थी कार्यक्रम को निलंबित कर दिया है, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान में फंसे हजारों अफगानों को फिर से बसाना है। पाकिस्तान में अस्थायी तौर पर रह रहे 25,000 अफगान अमेरिकी शरणार्थी कार्यक्रम के तहत अमेरिका भेजे जाने के पात्र हैं। यहां तक कि बाइडन प्रशासन भी इससे पीछे हट रहा था और उन्हें वापस लेने की जल्दी में नहीं था। ये 25,000 अफगान वर्षों से पाकिस्तान में रह रहे हैं, जिन्हें काबुल पर कब्जे के बाद वाशिंगटन के अनुरोध पर पाकिस्तान सरकार द्वारा यहां लाया गया था। उन्होंने अफगानिस्तान में नाटो और अमेरिकियों के साथ काम किया था, इसलिए यदि वे तालिबान शासन में अफगानिस्तान लौट गए, तो कभी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे।

चूंकि ट्रंप प्रशासन आव्रजन के मामले में सख्त रुख अपना रहा है, इसलिए पाकिस्तान को यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी कूटनीतिक लड़ाई लड़नी होगी कि ट्रंप अपने पूर्ववर्ती के निर्णय का सम्मान करें।

इसके अलावा, अमेरिका ने पाकिस्तान को दी जाने वाली विदेशी सहायता को पुनर्मूल्यांकन के लिए रोक दिया है। यह रोक 90 दिनों की है। वर्तमान में दुनिया की कई राजधानियों की तरह इस्लामाबाद में भी कोई पूर्णकालिक अमेरिकी राजदूत नहीं है और यह भी नहीं पता कि कब किसी को नामित किया जाएगा। इससे स्वास्थ्य क्षेत्र से लेकर कृषि और शिक्षा तक कई परियोजनाएं रुक गई हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे आर्थिक विकास से जुड़ी चार परियोजनाएं भी प्रभावित हुई हैं। यह देखना भी दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान और अमेरिका के सैन्य संबंध किस तरह से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अमेरिका के अफगानिस्तान से चले जाने के बाद से ही उसकी इस क्षेत्र में कोई खास दिलचस्पी नहीं रही है। अफगान युद्ध के दौरान दोनों देशों के सैन्य संबंध मजबूत हुए थे। लेकिन अब पाकिस्तान को कोई सैन्य सहायता नहीं मिल रही है। लगता है कि शुरुआत में ट्रंप का सैन्य नेतृत्व सतर्क रुख अपनाएगा, क्योंकि बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है कि राजनीतिक संबंध कैसे उभरते हैं।

सिसोदिया को भाजपा और कांग्रेस से मिलेगी टक्कर

अनन्या मिश्रा

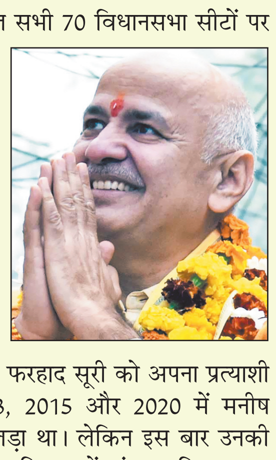

दिल्ली विधानसभा चुनाव के तहत सभी 70 विधानसभा सीटों पर 05 फरवरी को मतदान होना है। वहीं चुनाव के नतीजे 08 फरवरी को आएंगे। साथ ही यह भी पता चल जाएगा कि दिल्ली के सीएम की गद्दी पर किस पार्टी का नेता बैठेगा। वहीं खासतौर पर इस बार सभी की नजरें जंगपुरा विधानसभा सीट की ओर है। इस सीट से दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं भाजपा से इस सीट पर तरविंदर सिंह मारवाह और कांग्रेस ने फरहाद सूरी को अपना प्रत्याशी बनाया है। इससे पहले साल 2013, 2015 और 2020 में मनीष सिसोदिया ने पटपड़गंज से चुनाव लड़ा था। लेकिन इस बार उनकी सीट बदल गई है। दिल्ली के चुनावी इतिहास में जंगपुरा विधानसभा सीट पर आज तक भाजपा अपना परचम नहीं लहरा पाई है। साल 1993, 1998, 2003 और 2008 के चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। वहीं साल 2013, 2015, और 2020 में आप पार्टी के प्रत्याशी ने इस सीट पर झंडे गाड़े थे। हालांकि बीच-बीच में कई ऐसे मौके आए, जब भाजपा के उम्मीदवार ने विजेताओं को कांटे की टक्कर दी थी। लेकिन वह जीतने के लिए उतने वोट हासिल नहीं कर पाए थे। लेकिन इस बार समीकरण पूरी तरह से बदले हुए थे। क्योंकि भाजपा ने जंगपुरा सीट से तरविंदर सिंह मारवाह को चुनावी मैदान में उतारा है। सियासी जानकारों की मानें, तो जंगपुरा की जंग इस बार दिलचस्प हो सकती है। क्योंकि इस सीट से भाजपा की तरफ से उतरे तरविंदर सिंह मारवाह विधायक रह चुके हैं। लेकिन तब वह कांग्रेस में थे। तरविंदर सिंह मारवाह ने साल 1998, 2003 और 2008 में जीत दर्ज हो सकती है। तो वहीं कांग्रेस ने इस सीट से फरहार सूरी तो अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं आप पार्टी के मनीष सिसोदिया भी इस सीट से ताल ठोंक रहे हैं। हालांकि दिल्ली की सियासत में मनीष सिसोदिया बड़ा नाम हैं, ऐसे में उनको इसका फायदा मिल सकता है। आप पार्टी इस सीट से जीत की हैट्रिक लगा चुकी है। इसलिए सिसोदिया यह उम्मीद कर रहे हैं कि चौथी बार भी यह सीट आप पार्टी के खाते में जाएगी। बता दें कि पिछले 3 चुनावों से जंगपुरा की विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी का ही दबदबा है। साल 2020 में हुए विधानसभा चुनावों में आप प्रत्याशी प्रवीण कुमार ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भारतीय जनता पार्टी के इमप्रीत सिंह बख्शी को 16 हजार से अधिक वोटों से हराया था। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी तरविंदर सिंह मारवाह तीसरे नंबर पर थे। इसके अलावा साल 2015 के चुनाव में भी आप के प्रवीण कुमार ने भाजपा के मनिंदर सिंह धीर को 20 हजार वोटों से हराया था। इस चुनाव में भी कांग्रेस के मारवाह तीसरे स्थान पर रहे।

द्वारका सीट पर देखने को मिल रही दिलचस्प मुकाबला

दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार खासतौर पर लोगों की नजरें द्वारका विधानसभा सीट की ओर है। इस सीट पर पिछले कई सालों से आम आदमी पार्टी का कब्जा है। आप पार्टी ने एक बार फिर उसी प्रत्याशी पर भरोसा जताया है, जिसको पार्टी ने पिछली बार टिकट दिया था। दिल्ली की द्वारका सीट पर आप पार्टी ने विनय मिश्रा, भाजपा ने प्रद्युम्न सिंह राजपूत और कांग्रेस ने आदर्श शास्त्री को टिकट दिया है। बता दें कि दिल्ली की द्वारका विधानसभा सीट पर इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। इस सीट से चुनाव लड़ने वाले तीनों प्रत्याशी अनुभवी हैं। भाजपा के प्रद्युम्न सिंह राजपूत लगातार 6वीं बार इस सीट से अपना भाग्य आजमाने उतर रहे हैं। हालांकि इससे पहले साल 2009 और 2013 में भाजपा के प्रद्युम्न सिंह राजपूत को इस सीट से जीत मिली थी। लेकिन 2013 के बाद से लगातार उनको इस सीट से हार का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें, तो आप ने इस सीट से एक बार फिर विनय मिश्रा पर विश्वास जताया है। वर्तमान समय में विनय मिश्रा इस सीट से विधायक हैं। पहली बार में ही विनय मिश्रा ने द्वारका सीट पर जीत हासिल की थी। ऐसे में इस बार फिर आप प्रत्याशी विनय मिश्रा का इस सीट पर प्रदर्शन देखने लायक होगा। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली की द्वारका सीट से आदर्श शास्त्री को टिकट दिया है। बता दें कि साल 2015 में आदर्श मिश्रा आप पार्टी से विधायक बने थे। लेकिन बाद में उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ दिया था और कांग्रेस में शामिल हो गए थे। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में आदर्श शास्त्री को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में इस बार देखना दिलचस्प होगा कि इस बार आदर्श मिश्रा का प्रदर्शन कैसा रहने वाला है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली की द्वारका सीट पर आप ने फिर कब्जा जमाया था। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने विनय मिश्रा को टिकट दिया था। तो वहीं भाजपा ने प्रद्युम्न सिंह राजपूत को टिकट दिया था। वहीं कांग्रेस ने आदर्श शास्त्री को टिकट दिया था। इस दौरान आप पार्टी के उम्मीदवार विनय मिश्रा ने 71,003 वोट पाकर जीत हासिल की। भाजपा के प्रद्युम्न सिंह राजपूत को 56,616 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस के आदर्श शास्त्री को 6,755 वोट से ही संतोष करना पड़ा था। बता दें कि साल 2015 के विधानसभा चुनाव में आप पार्टी ने दिल्ली की द्वारका सीट पर जीत हासिल की थी। इस चुनाव में आप पार्टी ने इस सीट पर आदर्श शास्त्री को टिकट दिया था। लेकिन इस बाद आदर्श शास्त्री कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। 2015 के चुनाव में बीजेपी के प्रद्युम्न सिंह राजपूत को 40,363 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस के महाबल मिश्रा को 12,532 वोट से संतोष करना पड़ा था। वहीं आप के उम्मीदवार को 79,729 वोट मिले थे।

सर्दियों में स्किन का ख्याल रखता है गुड़, इन तीन तरीकों से करें इस्तेमाल

सर्दी के मौसम में जब आपकी स्किन रूखी व बेजान हो जाती है तो ऐसे में गुड आपकी स्किन को हाइड्रेटेड और ग्लोइंग बनाए रखता है। यह विटामिन, मिनरल और एंटी-ऑक्सीडेंट से भरपूर है जो आपकी स्किन को मॉइश्चराइज़ करने के साथ-साथ उसे एक्सफ़ोलिएट और हील भी करता है।

ठंड के मौसम में हम सभी गुड़ का सेवन जरूर करते हैं। यह शरीर को गरमाहट प्रदान करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि गुड़ ठंड के दिनों में आपकी स्किन का ख्याल भी रख सकता है। सर्दी के मौसम में जब आपकी स्किन रूखी व बेजान हो जाती है तो ऐसे में गुड आपकी स्किन को हाइड्रेटेड और ग्लोइंग बनाए रखता है। यह विटामिन, मिनरल और एंटी-ऑक्सीडेंट से भरपूर है जो आपकी स्किन को मॉइश्चराइज़ करने के साथ-साथ उसे एक्सफ़ोलिएट और हील भी करता है।

गुड़ को आप कई अलग-अलग तरीकों से अपने विंटर स्किन केयर रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं। तो चलिए आज इस लेख में हम आपको बता रहे हैं कि ठंड के दिनों में अपनी स्किन का ख्याल रखने के लिए आप गुड़ का इस्तेमाल किस तरह करें-

गुड़ और शहद से बनाएं फेस मास्क

ठंड के मौसम में अपनी स्किन की नमी को बनाए रखने और डेड स्किन सेल्स को हटाने के लिए आप गुड़ और शहद की मदद से फेस मास्क बनाकर इस्तेमाल करें।

आवश्यक सामग्री-

1 बड़ा चम्मच गुड़ पाउडर या कुचला हुआ

1 बड़ा चम्मच शहद

इस्तेमाल का तरीका-

सबसे पहले गुड़ को शहद के साथ मिलाकर पेस्ट बना लें।

अब इस मिश्रण को अपने चेहरे पर 10-15 मिनट तक लगाएं।

अंत में, गुनगुने पानी से चेहरा धो लें और स्किन को मॉइश्चराइज करें।

गुड़ से बनाएं लिप बाम

ठंड के मौसम में होंठों के रूखेपन या फटने की समस्या बेहद आम है। ऐसे में आप गुड़ की मदद से लिप बाम बनाएं। यह आपके होंठों की नमी को बनाए रखने में मदद करेगा।

आवश्यक सामग्री-

1 चम्मच गुड़

1 चम्मच घी या नारियल का तेल

इस्तेमाल का तरीका-

गुड़ को घी या नारियल के तेल के साथ मिक्स करें।

अब इसे अपने होठों पर लगाएं।

आप हर दिन इसका इस्तेमाल कर सकती हैं और सर्दियों में भी होंठों को मुलायम बनाए रख सकती हैं।

गुड़ से बनाएं स्क्रब

गुड़ की मदद से स्क्रब भी बनाया जा सकता है। आप इसके साथ ओट्स या चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं।

आवश्यक सामग्री-

1 बड़ा चम्मच गुड़

1 बड़ा चम्मच पिसा हुआ ओट्स या चीनी

1 बड़ा चम्मच जैतून का तेल

स्क्रब बनाने का तरीका-

सबसे पहले गुड़ को पिसे हुए ओट्स या चीनी के साथ मिक्स करें।

अब इसमें जैतून का तेल मिलाएं।

इसे अपने चेहरे या शरीर पर लगाकर मसाज करें और धो लें।

हेल्दी डाइट के बाद भी कम नहीं हो रहा बजन तो आज से ही शुरू कर दें यह काम, एक हफ्ते में दिखेगा असर

वेट लॉस करना चाहते हैं और इसके लिए एक्सरसाइज भी करते हैं। हेल्दी खाना भी खाते हैं। लेकिन फिर भी मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल रहा। इसके लिए कई बार लाइफस्टाइल की बहुत छोटी बातें जिम्मेदार होती हैं। इस बारे में फिटनेस कोच शितिजा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है और बताया कि कैसे वर्कआउट करने के बाद भी वजन कम नहीं हो रहा।

आखिर क्यों दिखता है बढ़ा हुआ वजन

अगर आपका वजन भी रोज एक किलो के करीब ज्यादा दिख रहा तो इसके लिए कई फैक्टर जिम्मेदार होते हैं।

-रात को हाई कार्बोहाइड्रेट वाला डिनर

-स्ट्रेस

-बहुत ज्यादा हैवी वर्कआउट, जिसकी वजह से मसल्स लॉस होने की बजाय स्ट्रेंथ पाती हैं।

-रात को देर से खाना

-पीरियड्स के दौरान भी कुछ महिलाओं का वजन बढ़ा हुआ दिखता है।

-अगर आपकी नींद ठीक से पूरी नहीं हो रही तो भी वेट गेन होगा।

-वेट नापते वक्त आपका पेट खाली होना चाहिए। अगर आप शौच के लिए जाने वाले हैं तो वजन ना तौलें। ऐसे वक्त में भी वेट ज्यादा दिखता है।

-ज्यादा नमक और सोडियम रिच फूड्स खाने की वजह से शरीर में वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम हो जाती है और वजन ज्यादा दिखने लगता है।

कैसे पता करें कि हो रहा वेट लॉस

-अगर आप वजन नापने वाली मशीन पर खड़े होने पर वजन घटा हुआ नहीं पाते तो घबराएं नहीं। रोज वजन घटने की बजाय बढ़ा हुआ दिख रहा तो इस तरह पता करें कि आपकी एक्सरसाइज असर दिखा रही है।

-आपके कपड़ों की साइज बदल गई है और फिटिंग चेंज हो गई है।

-शरीर ज्यादा फ्रेश और स्ट्रांग महसूस करता है। जैसे कि सीढ़ियां चढ़ते वक्त या फिर वेट ट्रेनिंग करना अब पहले से आसान लगता है।

रोज-रोज वजन फ्लक्चुएट हो रहा लेकिन लंबे समय में वजन घटा है तो इसका मतलब है कि आपकी डाइट और एक्सरसाइज असर दिखा रही है।

स्वेटर-शॉल पर आ गए हैं रोएं तो निकालने के लिए अपनाएं ये तरीके

गर्म कपड़ों में रोएं निकलने से हर कोई परेशान रहता है। एक-दो धुलाई के बाद वूलेन कपड़ों में रोएं निकल आते हैं। जिसकी वजह से महंगे से महंगा कपड़ा पुराना नजर आने लगता है। लेकिन आप कुछ आसान हैक्स की मदद से आप इनको आसानी से हटा सकते हैं।

दिसंबर और जनवरी का महीना आते-आते कई राज्यों में सर्दी ने जोर पकड़ लिया है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। सर्दी से बचने के लिए हम सभी ऊनी कपड़ों का सहारा लेते हैं। लेकिन गर्म कपड़ों में रोएं निकलने से हर कोई परेशान रहता है। एक-दो धुलाई के बाद वूलेन कपड़ों में रोएं निकल आते हैं। जिसकी वजह से महंगे से महंगा कपड़ा पुराना नजर आने लगता है। लेकिन आप कुछ आसान हैक्स की मदद से आप इनको आसानी से हटा सकते हैं। इसके साथ ही आपको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। जिससे कि इन कपड़ों में रोएं न लगें। वहीं रोएं की वजह से आपका कपड़ा खराब हो रहा है, तो आप कंघी वाली ट्रिक आजमा सकती हैं।

कपड़ों से क्यों निकलते हैं रोएं

कपड़ों को गलत तरीके से धोने या सुखाने से रोएं निकलने लगते हैं।

ऊनी कपड़े पहनकर सोने से भी कपड़ों में रोएं निकलने लगते हैं।

ऊनी कपड़ों को गर्म पानी से धोने से रोएं भी निकलने लगते हैं।

सस्ती और खराब क्वालिटी का ऊन होने पर रोएं निकल सकते हैं।

कंघी से हटाएं रोएं

आप कंघी की मदद से भी वूलेन कपड़ों से रोएं हटा सकती हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें किसी तरह का कोई खर्च नहीं आता है। आप रोएं वाली जगह पर कंघी को घुमाना होगा। ऐसे में कंघी में रोएं फंसकर साफ हो जाएंगे। ध्यान रखें कि रोएं निकालने के लिए पतली कंघी लेनी होगी।

इन ट्रिक्स से निकालें रोएं

आप पैकिंग टेप की सहायता से आसानी से रोएं निकाल सकते हैं। इसके लिए रोएं पर टेप लगाएं।

इसके अलावा वूलेन कपड़ों को विनेगर में भिगोकर रखें, इससे रोएं आसानी से निकल सकते हैं।

आप शेविंग रेजर की सहायता से भी रोएं निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि रोएं निकालते समय कपड़े को कोई नुकसान न हो।

वहीं अगर आपके पास लिंट रिमूवर है, तो यह बेस्ट ऑप्शन होगा।

ऐसे धोएं ऊनी कपड़े

बता दें कि बहुत सारे लोग ऊनी कपड़ों को गर्म पानी से धोते हैं, जिसकी वजह से कपड़ों में रोएं निकल आते हैं। बल्कि गर्म पानी से धोने से इसकी बनावट भी खराब हो जाती है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप वूलेन कपड़ों को गर्म पानी से धोएं। वहीं अगर आप वूलेन कपड़ों को वॉशिंग मशीन में धोते हैं, तो आपको वूल या डेलिकेट मोड ऑन करें। अगर आप हाथ से इन कपड़ों को धोते हैं, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। गर्म कपड़ों को सही तरीके से धोने से गर्म कपड़ों में रोएं की कोई परेशानी नहीं होती है।

साइकल चलाते समय न करें ये गलतियां

अधिकतर लोग खुद को फिट रखने के लिए साइकिल चलाना पसंद कर रहे है और फिटनेस के लिए इसे अपनी रूटीन में शामिल कर रहे है। वैसे भी फिट और एक्टिव रहने के लिए साइकिल चलाना बेस्ट माना जाता है। यदि नियमित रूप से साइकिल चलाई जाए तो इससे बॉडी की पूरी एक्सरसाइज होती है। और टोन्ड और परफेक्ट फिगर पा सकते है। लेकिन साइकिल चलाते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। वरना सेहत से जुड़ी अन्य समस्या हो सकती हैं।

- कुछ लोगों की आदत होती है कि वे बार-बार पानी पीते है, ये बिलकुल अच्छी बात है लेकिन साइकिल चलाते समय अधिक मात्रा में पानी नहीं पीना चाहिए। क्योंकि साइकिल चलाते वक्त अधिक मात्रा में पानी पीया जाएं तो इससे मतली की समस्या होने लगती है। वहीं ज्यादा पानी पीने से बार-बार पेशाब आएगी। जिससे पेट में दर्द हो सकता है। इसलिए साइकिल चलाते वक्त पानी न पीएं।
- साइकिल चलाना फिट रहने के लिए एक बेस्ट विकल्प है। इसलिए साइकिल चलाते वक्त फास्ट फूड या फिर जंक फूड से दूरी रखना ही बेहतर होता है, क्योंकि अनहेल्दी खाने से शरीर में फेट बढ़ता है। इससे आप सुस्त महसूस करेंगे।
- साइकिल चलाने से पहले स्ट्रेचिंग न करें। वैसे आमतौर पर वर्कआउट से पहले स्टेचिंग की सलाह दी जाती है। लेकिन साइकिल चलाने से पहले स्ट्रेचिंग न करें। इससे मांसपेशियां कमजोर हो सकती है और उनमें खिंचाव आ सकता है। यदि आप स्टेचिंग करना चाहते है तो कम से कम आधे घंटे पहले करें।
- कई बार ऐसा होता है कि हम साइकिल राइड को मजेदार बनाने के लिए स्टंट करना शुरू कर देते हैं। इससे एक्सीडेंट होने की संभावना अधिक रहती है।

सर्दियों में लहसुनी पालक का लुत्फ उठाएं

सर्दियों के दौरान हरी सब्जियां खाना काफी पौष्टिक माना जाता है। पालक खाना सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद होती। ठंड के मौसम में लहसुनी पालक का लुत्फ उठाएं, स्वाद इतना गजब सब करेंगे तारीफें।

ठंड के मौसम में साग, पालक और मेथी की सब्जी खूब खाई जाती है। सब्जी मंडी में इस समय पूरे बाजार में हरी सब्जियां नजर आती है। हरी सब्जियां सेहत के लिए काफी फायदेमंद होती है। पालक के सेवन करने से शरीर को कई पोषक तत्व मिलते हैं। पालक में भरपूर न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। इसमें आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, प्रोटीन और फाइबर मौजूद होता है। इस विंटर सीजन में लहसुनी पालक की सब्जी बनाएं, जो स्वाद और हेल्थ के लिए बढ़िया है। आइए आपको लहसुनी पालक रेसिपी बताते हैं।

लहसुनी पालक बनाने के लिए हमें क्या चाहिए?

- 1 बड़ा कटोरा पालक, उबालकर कटा हुआ
- 1 बड़ा चम्मच घी
- 1/4 छोटा चम्मच जीरा
- 2 बड़ा चम्मच कटा हुआ लहसुन
- 1 छोटा कटा प्याज
- 1 चम्मच कटी हरी मिर्च
- 2 साबुत सूखी लाल मिर्च
- 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर
- 1/4 चम्मच मिर्च पाउडर
- स्वादानुसार नमक

तड़का के लिए

- 1 बड़ा चम्मच शुद्ध घी
- 1/2 छोटा चम्मच जीरा
- 1 छोटा चम्मच कटा हुआ लहसुन
- 1 साबुत सूखी लाल मिर्च
- कटा हुआ टमाटर

लहसुनी पालक कैसे बनाएं

- सबसे पहले आप एक पैन में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, कटा हुआ लहसुन और साबुत सूखी लाल मिर्च डालें। कुछ समय तक भूने, फिर आप कटा हुआ प्याज डालें, जब तक यह ग्लोडन ब्राउन न हो जाए।

- अब कटी हुई हरी मिर्च, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डालें। कुछ सेकंड के लिए भूनें, फिर कटा हुआ पालक और स्वादानुसार नमक डालें। कुछ मिनट तक भूनते रहें, और परोसने के बर्तन में निकाल लें।

- फिर आफ तड़का के लिए शुद्ध घी, जीरा, कटा हुआ प्याज और साबुत सूखी लाल मिर्च के साथ तड़का तैयार करें। जब तक लहसुन सुनहरा भूरा ने हो जाए तब तक इसे भूनें।

- अब आप इस तैयार किए हुए तड़के को लहसुनी पालक में डाल दीजिए और कटे हुए टमाटर से गार्निश करें।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय प्रमुख समाचार

संसद में सार्थक चर्चा होनी चाहिए : उपराष्ट्रपति

नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को बजट सत्र की शुरुआत होने से पहले कहा कि संसद में व्यवधान का दौर खत्म करके सार्थक चर्चा की राह बनाई जानी चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग के 33वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश को ऐसे विपक्ष की जरूरत है, सहयोगी और सार्थक हो। उपराष्ट्रपति ने कहा कि संसद में ज्यादा चर्चा और बहस होनी चाहिए न कि उसे बाधित किया जाए। राज्यसभा सभापति ने महिला सशक्तिकरण पर बात करते हुए संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण दिए जाने के फैसले की तारीफ की और इसे ऐतिहासिक उपलब्धि करार दिया। उन्होंने कहा कि देश में अब ऐसा माहौल बन रहा है, जो महिलाओं की महत्वकांक्षाओं का भी समर्थन करता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बढ़ी हुई महत्वकांक्षाएं बड़ी चुनौतियां भी लेकर आती हैं और उन चुनौतियों से पार पाने के लिए ऊर्जा और सही दिशा होनी बहुत जरूरी है।

केजरीवाल ने जहर के दावे पर चुनाव आयोग को जवाब सौंपा

नईदिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप नेता मनीष सिसोदिया के साथ आज (31 जनवरी) यमुना नदी के पानी में जहर के विवाद को लेकर भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) से मिलने पहुंचे। केजरीवाल ने जहर के अपने दावे पर चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब सौंपा। यह तब हुआ जब चुनाव आयोग ने केजरीवाल को नोटिस जारी कर उनसे इस आरोप का सबूत मांगा कि हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में पानी की आपूर्ति में जहर मिलाया है। चुनाव आयोग के कार्यालय जाने से पहले केजरीवाल ने मीडिया से कहा कि दूसरे नोटिस की भाषा से संकेत मिलता है कि चुनाव आयोग ने पहले ही अपनी कार्रवाई तय कर ली है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग आप को अपनी आवाज उठाने के लिए निशाना बनाकर संदेशवाहक को गोली मार रहा है।

नायब सैनी के खिलाफ होनी चाहिए एफआईआर : केजरीवाल

नईदिल्ली। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि मैंने दिल्ली में जल संकट होने से रोका। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में जहरीला पानी भेजकर और दिल्ली में कृत्रिम जल संकट पैदा करने की कोशिश करके अपराध किया है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि चुनाव आयोग चुनाव नहीं कराता है, तो यह कदम विनाशकारी साबित होगा, खासकर चुनाव के दौरान। केजरीवाल ने कहा कि भले ही हमने कोई नियुक्ति नहीं की है, हम चुनाव आयोग के पास जा रहे हैं। हम अपने साथ तीन बोतल यमुना जल ले जा रहे हैं। 7 पीपीएम अमोनिया और उन्हें सौंप दिया। हम उन्हें देश के सामने वह पानी पीने की चुनौती देते हैं। 'आप' प्रमुख ने कहा, मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि हमारा संघर्ष सफल रहा है और यमुना में अमोनिया का स्तर जो 26-27 जनवरी से 7 पीपीएम था, अब घटकर 2.1 पीपीएम हो गया है।

भगवंत मान पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी का तंज

नईदिल्ली। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिल्ली स्थित आधिकारिक आवास कपूरथला हाउस की तलाशी को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने तंज कसा है। मनोज तिवारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी बेनकाब हो गई है। यह शराब और पैसा बांटकर लोगों को रिश्वत देना चाहती है। लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया है। उन्होंने कहा कि सामान गोदाम में रखा हुआ था लेकिन वह भी किसी दिल्ली भक्त मुखबिर ने पुलिस को बता दिया होगा। नकदी और शराब की बोतलें पकड़ी गई हैं। यही आप का चरित्र है। भाजपा सांसद ने दावा किया कि नुकसान का बोझ अरविंद केजरीवाल पर पड़ेगा। इसलिए, भगवंत मान इस बोझ को उतारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। दिल्ली ने अब तक देखा है कि आम आदमी पार्टी चुनाव जीतने के लिए या तो पैसा और शराब बांटती है या घुसपैठियों को वोटर बनाती है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग सतर्क है और मुझे पूरा विश्वास है कि भ्रष्टाचार के इस चरित्र को जनता नोटिस कर रही है।

बजट सत्र में शामिल होने नहीं मिली इंजीनियर राशिद को बेल

नईदिल्ली। जम्मू-कश्मीर के बारामूला निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय सांसद शेख अब्दुल रशीद तिहाड़ जेल में कथित दुर्व्यवहार के विरोध में शुक्रवार से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का ऐलान किया है। राशिद की पार्टी अवामी इत्तेहाद पार्टी (एआईपी) के नेता भी श्रीनगर के प्रताप पार्क में अपने नेता के साथ एकजुटता दिखाने के लिए भूख हड़ताल करेंगे। इंजीनियर राशिद के नाम से मशहूर राशिद 2017 के आतंकी-फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा गिरफ्तारी के बाद 2019 से जेल में बंद है। 22 जनवरी को राशिद ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर अपनी जमानत याचिका पर फैसला लेने की मांग की, जो एक ट्रायल कोर्ट में लंबित है इनकी याचिका अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह के 24 दिसंबर के आदेश के बाद आई, जिन्होंने उनकी जमानत याचिका पर फैसला देने से इनकार कर दिया।

बजट सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति का अभिभाषण, सरकार की उपलब्धियां गिनाईं

राष्ट्रपति मुर्मू ने दिया विकसित भारत का संदेश

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच संसद का बजट सत्र शुक्रवार को आरंभ हो गया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। उन्होंने सांसदों को संबोधित करते हुए देश को विकसित भारत का संदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने प्रयागराज महाकुंभ में हुए हादसे पर दुख जताया। राष्ट्रपति ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी श्रद्धांजलि दी।

उन्होंने बजट सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि महाकुंभ भारत की सांस्कृतिक परंपरा और सामाजिक चेतना का पर्व है। उन्होंने कहा, इस समय महाकुंभ का ऐतिहासिक पर्व चल रहा है। यह भारत की सांस्कृतिक परंपरा और सामाजिक चेतना का पर्व है। करोड़ों लोग स्नान कर चुके हैं। मौनी अमावस्या के दिन हुए हादसे पर दुख व्यक्त करती हूं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। राष्ट्रपति मुर्मू ने अभिभाषण में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन का भी उल्लेख किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। मनमोहन सिंह का बीते साल 26 दिसंबर को निधन हो गया था।

इससे पहले अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि संसद की इस बैठक को संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। अभी दो माह पहले हमने संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ मनाई है और कुछ दिन पहले ही भारतीय गणतंत्र ने 75 वर्षों की यात्रा भी पूरी की है। ये अवसर लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत के गौरव को नई ऊंचाई देगा। भारत की विकास यात्रा के इस अमृतकाल को आज मेरी सरकार अभूतपूर्व उपलब्धियों के माध्यम से नई ऊर्जा दे रही है। तीसरे कार्यकाल में तीन गुना तेज गति से काम हो रहा है। आज देश बड़े निर्णयों और नीतियों को असाधारण गति से लागू होते देख रहा है।

राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार करते हुए तीन करोड़ अतिरिक्त परिवारों को नए घर देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए पांच लाख 36 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाने की योजना है। जनजातीय समाज के पांच करोड़ लोगों के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान प्रारंभ हुआ है। इसके लिए 80 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया

है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के छह करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा देने का फैसला हुआ है। इन्हें हर वर्ष पांच लाख रुपये का हेल्थ कवर मिलेगा।

उन्होंने कहा, मेरी सरकार ने युवाओं की शिक्षा और उनके लिए रोजगार के नए अवसर तैयार करने पर विशेष फोकस किया है। मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा में वित्तीय सहायता देने के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना शुरू की गई है। एक करोड़ युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर भी दिए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि मेरी सरकार महिलाओं के नेतृत्व में देश को सशक्त बनाने में, यानी महिला के नेतृत्व वाले विकास में विश्वास करती है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा लोक सभा और विधान सभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 91 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को सशक्त किया जा रहा है। देश की 10 करोड़ से भी अधिक महिलाओं को इसके साथ जोड़ा गया है। इन्हें कुल नौ लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि बैंक लिंकेज के माध्यम से वितरित की गई है। हमारी बैंकिंग और डिजी पेमेंट सखियां दूर दराज के इलाकों में लोगों को वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। कृषि सखियां नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दे रही हैं और पशु सखियों के माध्यम से हमारा पशुधन मजबूत हो रहा है। ड्रोन दीदी योजना महिलाओं के आर्थिक और तकनीकी सशक्तिकरण का माध्यम बनी है। आज हमारा युवा स्टार्टअप्स, स्पोर्ट्स से लेकर स्पेस तक हर फ़ील्ड में देश का नाम रोशन कर रहा है। माय भारत पोर्टल के जरिये लाखों युवा राष्ट्र निर्माण के कार्यों से जुड़ रहे हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि मेरी सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए आधुनिक शिक्षा व्यवस्था तैयार कर रही है। कोई भी शिक्षा से वंचित ना रहे, इसीलिए मातृ भाषा में शिक्षा के अवसर दिए जा रहे हैं। विभिन्न भर्ती परीक्षाएं 13 भारतीय भाषाओं में आयोजित कर, भाषा संबंधी बाधाओं को भी दूर किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत की टीमों ने चाहे ओलंपिक हो, या फिर पैरालंपिक, हर जगह बेहतरीन प्रदर्शन किया है। हाल ही में विश्व शतरंज चैम्पियनशिप में भी भारत ने अपना परचम लहराया है। फिट इंडिया मूवमेंट चलाकर हम सशक्त युवाशक्ति का निर्माण कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा, आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत के योगदान को आगे बढ़ाते हुए इंडिया एआई मिशन प्रारम्भ किया गया है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन से भारत, इस फ्रंटियर टेक्नोलॉजी में दुनिया के अग्रणी देशों की पंक्ति में स्थान बना सकेगा। उन्होंने कहा, कोविड और उसके बाद के हालात एवं युद्ध जैसी वैश्विक चिंताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने जो स्थायित्व एवं लचीलापन दिखाया है, वो उसके सशक्त होने का प्रमाण है। मेरी सरकार ने व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

उन्होंने कहा कि दशकों तक हमारे देश के रेहड़ी-पटरी पर दुकान लगाकर आजीविका चलाने वाले भाई-बहन बैंकिंग व्यवस्था से बाहर रहे। आज उन्हें पीएम स्वनिधि योजना का लाभ मिल रहा है। डिजिटल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड के आधार पर उनको बिजनेस बढ़ाने के लिए और लोन मिलता है। आज भारत डिजिटल टेक्नॉलजी की फील्ड में एक प्रमुख ग्लोबल प्लेयर के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। दुनिया के बड़े देशों के साथ ही भारत में 5जी सर्विसेस की शुरुआत इसका एक बड़ा उदाहरण है। राष्ट्रपति ने कहा कि मेरी सरकार ने डिजिटल टेक्नॉलजी को सामाजिक न्याय और समानता के एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया है। डिजिटल पेमेंट कुछ लोगों या कुछ वर्गों तक सीमित नहीं है। भारत में छोटे से छोटा दुकानदार भी इस सुविधा का लाभ उठा रहा है। तेजी से डिजिटाइज होते हमारे समाज में आज राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण विषय साइबर सिक्योरिटी है। डिजिटल फ्रॉड, साइबर-क्राइम और डीप फेक जैसी टेक्नॉलजी सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती भी बनी है।

बजट सत्र से पहले बोले प्रधानमंत्री मोदी

...जब सत्र से पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं भड़की, आग लगाने की कोशिश नहीं हुई

नई दिल्ली। संसद के बजट सत्र पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन के बाहर पत्रकारों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नवाचार, समावेशन और निवेश लगातार हमारी आर्थिक गतिविधि के रोडमैप का आधार रहे हैं। इस सत्र में हमेशा की तरह कई ऐतिहासिक बिल पर सदन में चर्चा होगी और व्यापक मंथन के साथ वो राष्ट्र की ताकत बढ़ाने वाले कानून बनेंगे।

विपक्ष पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से लेकर अब तक शायद यह पहला, संसद का सत्र है, जिसके एक दो दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं भड़की है, विदेश से आग लगाने की कोशिश नहीं हुई है। उन्होंने कहा, मैं 2014 से देख रहा हूं कि हर सत्र से पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते थे और यहां उन्हें हवा देने वालों की कोई कमी नहीं है। 10 साल बाद यह पहला सत्र मैं देख रहा हूं, जिसमें किसी भी विदेशी कोने से कोई चिंगारी नहीं भड़काई गई।

उन्होंने कहा, आज बजट सत्र के प्रारंभ में मैं समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी को प्रणाम करता हूं। ऐसे अवसर पर सदियों से हमारे यहां मां लक्ष्मी का पुण्य स्मरण किया जाता है। मां लक्ष्मी हमें सिद्धि और विवेक देती हैं। समृद्धि और कल्याण भी देती हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्गीय समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे।

पीएम मोदी ने कहा कि हमारे गणतंत्र ने 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह देश के प्रत्येक नागरिक के लिए बहुत गर्व की बात है। इस देश के लोगों ने मुझे तीसरी बार ये जिम्मेदारी दी है और ये इस तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है। मैं विश्वास से कह सकता हूं कि 2047 में जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत का जो संकल्प इस देश ने लिया है ये बजट सत्र, यह बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा, नई ऊर्जा देगा कि देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तब विकसित होकर रहेगा। 140 करोड़ देशवासी अपने सामूहिक प्रयासों से इस संकल्प को पूरा करेंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा, तीसरे कार्यकाल में हम मिशन मोड में देश को सर्वांगीण विकास की दिशा में चाहे वह भौगोलिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या आर्थिक भिन्न-भिन्न संदर्भ में हो, हम सर्वांगीण विकास के संकल्प को लेकर मिशन मोड में आगे बढ़ते जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि नवाचार, समावेशन और निवेश लगातार हमारी आर्थिक गतिविधि के रोडमैप का आधार रहे हैं। इस सत्र में हमेशा की तरह कई ऐतिहासिक बिल पर सदन में चर्चा होगी और व्यापक मंथन के साथ वो राष्ट्र की ताकत बढ़ाने वाले कानून बनेंगे। विशेषकर नारीशक्ति के गौरव को पुन: प्रस्थापित करना, पंथ-संप्रदाय के भेद से मुक्त होकर हर नारी को सम्मानपूर्ण जीवन और समान अधिकार मिले, इस दिशा में इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे।

पीएम मोदी ने कहा कि इस बजट सत्र में सभी सांसद विकसित भारत को मजबूती देने के लिए, अपना योगदान देंगे। विशेषकर जो युवा सांसद हैं, उनके लिए तो ये सुनहरा अवसर है, क्योंकि वो सदन में जितनी जागरूकता और भागीदारी बढ़ाएंगे, विकसित भारत के फल उनकी नजर के सामने देखने को मिलेंगे। इसलिए, युवा सांसदों के लिए ये एक अनमोल अवसर है। मैं आशा करता हूं कि हम देश की आशा-आकांक्षाओं के इस बजट सत्र में खरे उतरेंगे।

खेल प्रमुख समाचार

केरल के जलज सक्सेना ने रणजी ट्रॉफी में रचा इतिहास

तिरुअनंतपुरम। शुक्रवार 31 जनवरी को तिरुअनंतपुरम के स्पोर्ट्स हब इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में केरल और बिहार के बीच रणजी ट्रॉफी का मुकाबला खेला जा रहा है। वहीं इस मुकाबले में केरल टीम के जलज सक्सेना ने इतिहास रच दिया। दरअसल, जलज ने रणजी ट्रॉफी एलीट 2024-25 में अपने आखिरी लीग मैच में केरल की ओर से खेलते हुए बिहार के 5 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। ये उनकी गेंदबाजी का ही कहर था कि बिहार की टीम पहली पारी में 23.1 ओवर में 64 रन पर ढेर हो गई। बिहार को फॉलोऑन खेलना पड़ा। जलज सक्सेना ने 7 ओवर में 19 रन देकर 5 विकेट झटके। इससे पहले केरल ने पहली पारी में 101.2 ओवर में 351 रन बनाए थे।

वहीं जलज ने बिहार केखिलाफ 5 विकेट लेकर रणजी ट्रॉफी में नया रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने रणजी में 31वीं बार पांच बार विकेट लिए हैं। ये मौजूदा गेंदबाजों में सबसे ज्यादा है। टूर्नामेंट के इतिहास में केवल चार अन्य गेंदबाजों ने उनसे ज्यादा बार पांच विकेट झटके हैं। ये पहली बार है जब जलज ने बिहार के खिलाफ पांच विकेट लिए हैं। बिहार के खिलाफ 5 विकेट चटकाते ही वह 19वीं विपक्षी टीमों के खिलाफ 5 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उनसे पहले इतनी टीमों के खिलाफ किसी भी गेंदबाज ने 5 या उससे ज्यादा विकेट नहीं चटकाए हैं। 38 वर्षीय जलज ने इस तरह पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज पंकज सिंह (18) के रणजी ट्रॉफी में सबसे ज्यादा टीमों के खिलाफ पांच विकेट लेने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। रणजी ट्रॉफी में जलज सक्सेना के विकेटों की संख्या भी 416 हो गई। इससे वह रणजी ट्रॉफी में संयुक्त रूप से 9वें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/ प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 740 अंक उछला निफ्टी 23,500 के पार

नईदिल्ली। भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स 31 जनवरी को लगातार चौथे दिन में बढ़त के साथ बंद हुए। इकोनॉमिक सर्वे के चलते आज बाजार में रौनक देखने को मिली। सेंसेक्स 740.76 अंक या 0.97 प्रतिशत की बढ़त के साथ 77,500.57 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 258.90 अंक या 1.11 प्रतिशत चढ़कर 23,508.40 पर बंद हुआ। कुल 2,635 शेयर बढ़त में रहे, 1,131 शेयरों में गिरावट आई, जबकि 120 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। निफ्टी पर टॉप गेनर्स में टाटा कंज्यूमर, ट्रेंट, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, नेस्ले इंडिया और एलएंडटी शामिल रहे, जबकि नुकसान झेलने वाले शेयरों में भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फिनसर्व, अपोलो हॉस्पिटल्स और जेएसडब्ल्यू स्टील रहे। सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑयल एंड गैस, पावर, पीएसयू, रियल्टी और एफएमसीजी 2% तक चढ़े।

इकोनॉमिक सर्वे में 6.3-6.8% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान

नईदिल्ली। आर्थिक समीक्षा में अगले वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की ग्रोथ रेट 6.3 से 6.8 फीसदी रहने अनुमान लगाया जा सकता है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन और उनके दल की लिखित आर्थिक समीक्षा 2024-25 शुक्रवार दोपहर संसद में पेश गई। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुमान के अनुसार, कमजोर विनिर्माण व निवेश के कारण भारत की जीडीपी के चालू वित्त वर्ष 2024-25 में 6.4 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है, जो चार साल का निम्नतम स्तर है। यह पिछले वर्ष की आर्थिक समीक्षा में अनुमानित 6.5-7 प्रतिशत की वृद्धि दर तथा भारतीय रिजर्व बैंक के 6.6 प्रतिशत के अनुमान से भी कम है।

बजट में रियल एस्टेट सेक्टर को मिल सकती है बड़ी राहत

नईदिल्ली। बजट में रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। रियल एस्टेट को बड़ा बूस्ट संभव है। सरकार होम लोन पर टैक्स छूट बढ़ाने, सस्ते घरों के डेवलपर्स को प्रोत्साहन देने और रियल्टी सेक्टर को जीएसटी में राहत देने जैसे कदम उठा सकती है। साथ ही स्टाम्प ड्यूटी रेट के सरलीकरण और प्रोजेक्ट्स के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस पर भी अहम घोषणा संभव है। घर खरीदने की क्षमता बढ़ाने के लिए धारा 24(बी) के तहत होम लोन ब्याज कटौती 2 लाख रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। किफायती घरों की बिक्री को बढ़ावा देने को लिए अधिक से अधिक डेवलपर्स को आकर्षित करने के लिए किफायती आवास परियोजनाओं के लिए सेक्शन 80-IBA के लाभों को मार्च 2029 तक बढ़ाया जाना चाहिए। जीएसटी दर का युक्तिसंगत बनाना चाहिए। रियल एस्टेट को इंडस्ट्री का दर्जा मिलना चाहिए।

ओला इलेक्ट्रिक ने लॉन्च किए 8 Gen 3 स्कूटर

नईदिल्ली। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर शुक्रवार को बीएसई में इंट्रा-डे ट्रेड में 14.4% की बढ़त के साथ रु. 76.50 पर पहुंचे। कंपनी ने शुक्रवार को अपने S1 पोर्टफोलियो में जेनरेशन 3 फीचर्स के साथ 8 नए स्कूटर लॉन्च किए, जिसमें मास और प्रीमियम सेगमेंट शामिल हैं। कंपनी के अनुसार, Gen 3 प्लेटफॉर्म में Gen 2 की तुलना में 20% अधिक पावर, 11% कम लागत लगी है और 20% ज्यादा रेंज दी गई है। ओला इलेक्ट्रिक ने जनवरी 2025 में भारत के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में 25% बाजार हिस्सेदारी के साथ फिर से लीडर की पोजीशन हासिल की। वहान डेटा के अनुसार, कंपनी ने जनवरी में 22,656 वाहन रजिस्टर किए, जो महीने-दर-महीने आधार पर 65% की वृद्धि है। दिसंबर 2024 में बजाज ऑटो ने ईवी टू-व्हीलर बाजार में 25% की हिस्सेदारी के साथ टॉप पोजीशन हासिल की थी।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट से मिल सकती हैं कई सौगातें

(गतांक से आगे...)

प्रह्लाद सबनानी

वित्तीय वर्ष 2024-25 की प्रथम तिमाही में सम्पन्न हुए लोक सभा चुनाव के चलते देश में पूंजीगत खर्चों में कमी दिखाई दी है। इसीलिए अब लगातार यह मांग की जा रही है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन कानून को शीघ्र ही लागू किया जाना चाहिए क्योंकि बार बार देश में चुनाव होने से केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा आचार संहिता के लागू होने के चलते अपने बजटीय खर्चों को रोक दिया जाता है जिससे देश का आर्थिक विकास प्रभावित होता है। अत: वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लोक सभा में पेश किए जाने वाले बजट में पूंजीगत खर्चों को बढ़ाने पर गम्भीरता दिखाई जाएगी। हालांकि वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में 7.50 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत खर्चों का प्रावधान किया गया था, वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 10 लाख करोड़ रुपए एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में 11.11 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत खर्चों का प्रावधान किया गया था। अब वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कम से कम 15 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत खर्चों का प्रावधान किये जाने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है। इससे देश में धीमी पड़ रही आर्थिक गतिविधियों को तेज करने में सहायता मिलेगी और रोजगार के करोड़ों नए अवसर भी निर्मित होंगे, जिसकी वर्तमान समय में देश को अत्यधिक आवश्यकता भी है।

विभिन्न राज्यों द्वारा चलायी जा रही फ्रीबीज की योजनाओं पर भी अब अंकुश लगाए जाने के प्रयास किए जाने चाहिए। इन योजनाओं से देश के आर्थिक विकास को लाभ कम और नुकसान अधिक होता है। केरल, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं दिल्ली की

स्थिति हम सबके सामने है। इस प्रकार की योजनाओं को चलाने के कारण इन राज्यों के बजटीय घाटे की स्थिति दयनीय स्थिति में पहुंच गई है। पंजाब तो किसी समय पर देश के सबसे सम्पन्न राज्यों में शामिल हुआ करता था परंतु आज पंजाब में बजटीय घाटा भयावह स्थिति में पहुंच गया है। जिससे ये राज्य आज पूंजीगत खर्चों पर अधिक राशि व्यय नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इन राज्यों की न तो आय बढ़ रही है और न ही बजटीय घाटे पर नियंत्रण स्थापित हो पा रहा है।

पिछले कुछ समय से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी कम हो रहा है। यह सितम्बर 2020 तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद का 4.3 प्रतिशत था जो अब गिरकर सकल घरेलू उत्पाद का 0.8 प्रतिशत के स्तर तक नीचे आ गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में इस विषय पर भी गम्भीरता से विचार किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2019 के बजट में कोरपोरेट कर की दरों में कमी की घोषणा की गई थी, जिसका बहुत अच्छा प्रभाव विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर पड़ा था और सितम्बर 2020 में तो यह बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 4.3 प्रतिशत तक पहुंच गया था। अब एक बार पुन: इस बजट में कोरपोरेट कर में कमी करने पर भी विचार किया जा सकता है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर निर्मित करने वाले उद्योगों को भी कुछ राहत प्रदान की जा सकती है क्योंकि आज देश में रोजगार के करोड़ों नए अवसर निर्मित करने की महती आवश्यकता है। विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को विशेष सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं। हां, साथ में तकनीकी आधारित उद्योगों को भी बढ़ावा देना होगा क्योंकि वैश्विक स्तर पर भी हमारे उद्योगों को हमें प्रतिस्पर्धी बनाना है। ग्रामीण इलाकों में आज भी भारत की लगभग 60 प्रतिशत आबादी निवास करती है अत: कृषि क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर एवं लघु उद्योगों पर अधिक ध्यान इस बजट के माध्यम से दिया जाएगा, ताकि रोजगार के अवसर ग्रामीण इलाकों में ही निर्मित हों और नागरिकों के शहर की ओर हो रहे पलायन को रोका जा सके।

मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में कार्यकर्ताओं में भरा जोश और कहा -अब रायपुर में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना है ताकि विकास तेज गति से हों

भाजपा के प्रत्याशियों को जिताएं,विकास की गारंटी हमारी: सीएम साय

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर शहर के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी नगर निगम चुनाव में महापौर पद और सभी 70 पार्षद प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील करते हुए कहा है कि जनता भाजपा के पक्ष तैयार खड़ी है जनता विकास चाहती है। साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बने 13 महीने हुए हैं और 13 महीने में ही भाजपा सरकार ने जो काम किए हैं, उसे जनता ने देखा है। साय शुक्रवार को राजधानी के स्व. बलबीरसिंह जुनेजा इनडोर स्टेडियम में आयोजित भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि 2023 से पहले कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ की जो दुर्दशा हुई, वह सभी को मालूम है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा, जहाँ कांग्रेस की सरकार ने भ्रष्टाचार नहीं किया, घोटाला नहीं किया। उन घोटालेबाजों का आज क्या हाल हुआ है, यह प्रदेश देख रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ के भविष्य, हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली कांग्रेस की सरकार में पीएससी तक में भी भ्रष्टाचार हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश को आश्वस्त किया था कि भाजपा की सरकार बनेगी तो पीएससी घोटाले की जाँच सीबीआई से कराई जाएगी और आज पीएससी घोटाले की जाँच सीबीआई कर रही है और उसके जो दोषी हैं, वह सभी जेल के अंदर हैं और जो अन्य दोषी हैं, उन्हें जेल जाना होगा। साय ने कहा कि आज कांग्रेस सरकार की सरपरस्ती में हुए तमाम घोटालों के सभी घोटालाबाज जेल के अंदर हैं। उनकी जमानत याचिकाएँ भी बार-बार खारिज हो रही है। कांग्रेस के राज में पूरा छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बन गया था। प्रदेश की जनता का विश्वास प्रदेश की कांग्रेस सरकार से उठ गया था। इन 13 महीनों में जब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी तो हमने प्रदेश के 3 करोड़ छत्तीसगढ़िया के विश्वास को जीतने का काम किया है। आज 3 करोड़ छत्तीसगढ़ियों का विश्वास भाजपा की सरकार के प्रति है। मोदी की गारंटी में जो वादे हमने किए थे, उन वादों को पूरा किया है। चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे किसानों से ?3100 प्रति क्विंटल की दर पर प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी, 2 वर्षों के बकाया बोनस का भुगतान हो, 70 लाख से अधिक माताओं एवं बहनों को महतारी वंदन योजना के तहत ?1000 प्रतिमाह दिया जा रहा है। यह सभी कार्य हो रहा है। आज आदिवासी क्षेत्र में तेंदूपत्ता खरीदी ?4000 से बढ़कर 5500 रु. प्रति मानक बोरा कर दिया है।

रायपुर के विकास के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे : मीनल चौबे

भाजपा की महापौर प्रत्याशी मीनल चौबे ने कहा कि रायपुर नगर निगम से कांग्रेस को जड़ से उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। 11 फरवरी को आप सभी निकाय चुनाव में कमल फूल छाप पर बटन दबाकर भाजपा को जिताएंगे। यह गौरव और हर्ष की बात है अब रायपुर शहर की प्रथम महिला भाजपा की होगी। यह चुनाव मीनल चौबे नहीं, भाजपा की हर महिला कार्यकर्ता लड़ेगी और जीतकर हर महिला महापौर होगी। श्रीमती चौबे ने कहा कि भाजपा कैडर बेस पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। पार्टी ने मुझ जैसी एक सामान्य कार्यकर्ता को महापौर प्रत्याशी के लिए अवसर प्रदान किया। वहीं दूसरी तरफ, कांग्रेस की महापौर प्रत्याशी कौन है? उन्हें अपने पति के दम पर टिकट दिया गया है। कांग्रेस में एक भी योग्य महिला नहीं मिली जिसे प्रत्याशी बनाया जा सके। श्रीमती चौबे ने कहा कि पिछले 15 वर्षों से रायपुर नगर निगम में कांग्रेस का शासन रहा और इस दौरान केवल घोटालों और भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा। जनता विकास कार्यों के लिए तरसती रही।

भाजपा के कार्यकताओं का जोश हाई : देव

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए कहा कि रायपुर नगर निगम चुनाव का शंखनाद हो चुका है। आज सभी नगर निगम निकायों के भाजपा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होने जा रहा है। जिस तरीके से सभी कार्यकर्ताओं ने परिश्रम की पराकाष्ठा कर लगातार विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और रायपुर दक्षिण के उपचुनाव में जीत दिलाई, भाजपा के सभी संगठनात्मक कार्यक्रमों में सक्रिय सहभागिता निभाई और जनता-जनार्दन के आशीर्वाद से सिर्फ 5 वर्ष में ही छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के कुशासन से मुक्त किया है। देव ने कहा कि भाजपा ने ठाना है, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भाजपा का परचम फहराना है। रायपुर में हमारे महापौर और सभी पार्षद प्रत्याशियों की विजय सुनिश्चित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मात्र 1 साल 2 महीने में ही आम जनता तक पहुँचा है। विधानसभा चुनाव के पूर्व जो-जो वादे हमने किए थे, वह एक साल में ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने उनके वादों को पूरा करने का काम किया है इसलिए जनता का विश्वास और प्यार भाजपा के साथ है। देव ने कहा कि जनता ने ठान लिया है कि वह नगरीय निकाय चुनाव में और त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में भाजपा के पक्ष में ही मतदान करेगी।

अटलजी के सपने को साकार करने और रायपुर को सँवारने के लिए 71 कमल चाहिए : साव

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि रायपुर के कार्यकर्ताओं ने अपने दम से, अपनी मेहनत से सांसद बनाया है, इस बार चारों विधानसभा से विधायक बनाए है, लेकिन 15 साल हो गए हैं, रायपुर में भाजपा का महापौर नहीं बना है। साव ने कहा कि एक-एक कार्यकर्ता को आज कार्यकर्ता सम्मेलन से संकल्प लेकर जाना है कि जब तक रायपुर में भाजपा का महापौर नहीं बनाएंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। आप सब इस बार 15 तारीख को रायपुर में कमल खिलाएंगे, हम सभी रायपुर के कार्यकर्ता सम्मेलन में आज यह संकल्प लेते हैं। 15 फरवरी को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को रायपुर में कमल जिताकर यह संकल्प लेने का यह अवसर है। इस बार रायपुर से 71 कमल जिताना है। रायपुर को राजधानी हमने बनाया है, लेकिन 5 सालों में रायपुर को दोनों हाथ से लूटने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। अटल जी के सपने को साकार करने के लिए जिस रायपुर को हमने राजधानी बनाया, उसको सँवारने के लिए 71 कमल चाहिए।

बृजमोहन अग्रवाल दिल्ली विधानसभा चुनाव में कूदे

रायपुर। रायपुर से लोकसभा सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल ने भारतीय जनता पार्टी की कार्य योजना के तहत दिल्ली की मंगोलपुरी विधानसभा के रोहिणी मंडल में विधानसभा चुनाव की दृष्टि से शक्ति प्रमुखों की बैठक में भाग लेकर चुनावी रणनीति पर चर्चा की। सांसद महोदय ने चुनाव प्रचार के दौरान मंडल अध्यक्ष और निगम पार्षद से चुनाव प्रचार की रूपरेखा जानी। सांसद श्री अग्रवाल ने शक्ति प्रमुखों का मार्गदर्शन करते हुए उन्हें हर पोलिंग बूथ पर पन्ना प्रमुखों की बैठक लेकर घर-घर जनसंपर्क करने के लिए कहा। उन्होंने कहा की मंडल पदाधिकारी हर वोटर तक मतदाता पर्ची पहुंचना सुनिश्चित करें। साथ ही केजरीवाल सरकार की विफलताओं एवं भ्रष्टाचार को हर मतदाता को बताने का आह्वान भी किया। श्री अग्रवाल ने दिल्ली के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार बनाकर विकास का विकास का मार्ग प्रशस्त करने की अपील मतदाताओं से की। लगातार 9 चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बना चुके सांसद अग्रवाल ने कहा कि पिछले दस साल में केजरीवाल सरकार के केंद्र से लगातार झगड़ा और टकराव के कारण दिल्ली का विकास पूरी तरह बाधित हो गया है। इसलिए अब आप दा को भगाने के लिए कमल फूल का बटन दबाने का आह्वान श्री अग्रवाल ने किया। गौरतलब है कि मंगोलपुरी विधानसभा से राजकुमार चौहान बीजेपी के प्रत्याशी हैं।

भाजपा का झंडा अभियान आज

जल्द जारी होगा जनघोषणा और आरोप पत्र: सवन्नी

रायपुर । छत्तीसगढ़ भाजपा नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जल्द ही घोषणा पत्र जारी करेगी। साथ ही भाजपा जनता के बीच ही आरोप पत्र भी लेकर आएगी। भाजपा का जनघोषणा पत्र प्रदेश की निकायों के विकास और भाजपा के सुशासन की अवधारणा से पूरिपूर्ण होगा। सवन्नी ने कहा कि एक फरवरी को प्रदेशभर के भाजपा कार्यकर्ता अपने घरों में भाजपा का झंडा लगाने का अभियान चलाएंगे।

उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता घर-घर विष्णुदेव साय सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर जनता के बीच जा रहे है, साथ ही कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान निकायों में हुए भ्रष्टाचार और विकास कार्य की अनदेखी का मुद्दा भी जनता के बीच उठाया जाएगा। कांग्रेस की पूर्ववर्ती भूपेश सरकार में नगरीय निकायों में विकास कार्य शून्य रहा।

कांग्रेस के निकायों के जनप्रतिनिधियों ने विकास कार्यों में भ्रष्टाचार को अंजाम दिया। जहां भाजपा के सभी पार्षद पद के उम्मीदवारों ने एक साथ अपने मेयर और अध्यक्षों के साथ नामांकन किया। वहीं कांग्रेस के पार्षदों ने अलग-अलग नामांकन भरे। हालात यह है कि नामांकन के अंतिम दिन तक कांग्रेस निकायों के प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं कर पाई। कांग्रेस नगरीय निकाय चुनाव में भी अंतर्कलह से जूझ रही है।

भाजपा के समर्थन में आई लीला जैन

रायपुर। रायपुर नगर निगम चुनाव में नामांकन वापसी के अंतिम दिन वार्ड क्रमांक 58, शाहिद पंकज विक्रम से निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी लीला तेजा जैन ने भाजपा की प्रत्याशी श्रीमती स्वप्निल मिश्रा के समर्थन में अपना नामांकन वापस ले लिया। इस महत्वपूर्ण निर्णय में रायपुर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस अवसर पर श्री अग्रवाल ने लीला तेजा जैन के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और विकास एवं सुशासन के संकल्प को पूरा करने के लिए संगठन को मजबूत करना आवश्यक है। लीला तेजा जैन ने भाजपा प्रत्याशी को समर्थन देने का निर्णय जनता की एकजुटता और वार्ड के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए लिया। उन्होंने विश्वास जताया कि भाजपा की नीतियां वार्ड के नागरिकों के हित में कारगर साबित होंगी।

भोरमदेव अभ्यारण्य बनेगा टाइगर रिजर्व

बृजमोहन की मांग पर केंद्रीय वन मंत्री ने दिए निर्देश

रायपुर। छत्तीसगढ़ के वन्यजीव संरक्षण को एक नई दिशा देते हुए भोरमदेव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। यह महत्वपूर्ण निर्णय रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल की पहल पर लिया गया है। उनकी मांग पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार को निर्देश जारी किए हैं।

सांसद बृजमोहन ने केंद्रीय वन मंत्री को लिखे पत्र में कहा था कि भोरमदेव अभ्यारण्य, जो कान्हा टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, वन्यजीव संरक्षण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हङ्गष्ट ने 28 जुलाई 2014 को इस क्षेत्र को टाइगर रिजर्व बनाने की अनुशंसा की थी। इसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड ने भी इसकी मंजूरी दी थी।

केंद्रीय वन मंत्री के माध्यम से हङ्गष्ट ने राज्य सरकार को निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिससे इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है। भोरमदेव टाइगर रिजर्व के रूप में यह क्षेत्र कान्हा-अचानकमार कारीडोर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगा, जिससे बाघों के सुरक्षित आवागमन को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, बारासिंगा सहित अन्य दुर्लभ वन्यजीवों के संरक्षण में भी यह क्षेत्र अहम भूमिका निभाएगा।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

2500 गरीब मजदूरों को थाने में बैठाना अत्याचार : बैज

रायपुर । भाजपा सरकार के इशारे पर 2500 गरीब मजदूरों को उनके कमरों से उठा कर थाने में लाकर बैठाया जाना गरीबों पर अत्याचार है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा सरकार गरीबों को परेशान कर रही है। देश के एक राज्य से दूसरे राज्य में रोजी-रोटी कमाने जाना गुनाह नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ के भी हजारों लोग अन्य प्रांतों में रोजगार के लिये जाते है। भारत का संविधान अपने हर नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में बसने और रोजगार करने आने जाने की छूट देता है। भाजपा सरकार अपनी राजनीति करने के लिए गरीबों को निशाना बना रही है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि जिन 2500 लोगों को उठा करके थाने लाई थी उनमें से 95 प्रतिशत लोग हिन्दू है। उनके अपने गृह जिलों, गृह राज्यों के आधार कार्ड, मतदाता कार्ड है, सभी भारत के नागरिक है। उनका कसूर केवल इतना है कि वे गरीब है तथा रोजी-रोटी के लिए छत्तीसगढ़ आयें है, उनके साथ सरकार ने अपराधियों जैसे बर्ताव किया। 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' का नारा देने वाली भाजपा एक राष्ट्र, एक नागरिकता के संवैधानिक प्रावधान का भी सम्मान नहीं कर पा रही है। सरकार अपनी अमानवीय कृत्य के लिए इन गरीबों से सार्वजनिक माफी मांगे।

भाजपा हार के डर से सत्ता का दुरुपयोग कर रही : कांग्रेस

रायपुर। भाजपा टिकिट बंटने के बाद जिस प्रकार से भाजपा कार्यकर्ता बगावत पर उतर आये है, उसके कारण भाजपा बौखला गयी है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी स्थानीय निकाय चुनाव में बेईमानी पर उतर आई है। सरकार के दबाव और भ्रष्टाचार के पैसे का दुरूपयोग करके कांग्रेस प्रत्याशियों को मैदान से हटाने, डराने धमकाने का षडयंत्र पूरे प्रदेश में चल रहा है। धमतरी के कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी विजय गोलछा का नामांकन साजिश करके रद्द किया गया, प्रदेश के अन्य निगमों, नगर पंचायतों में भी कांग्रेस प्रत्याशियों को चुनाव से पहले ही हटाने की साजिश रची गयी है। सरकार के तमाम हथकंडो के बाद भी कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। जनता कांग्रेस के साथ है, भाजपा कोई भी षडयंत्र करले उसकी हार तय है। टिकिट बटंने के बाद भाजपा में बगावत है नगरी में भाजपा कार्यालय जला दिया गया प्रदेश के आधा दर्जन क्षेत्रों में भाजपा नेताओं के पुतले फूंके जा रहे। भाजपा की टिकिट सत्ता के दलाल बेच रहे, भाजपा कार्यकर्ताओं में हताशा है प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा के उम्मीदवार जो चुनाव लड़ने के अयोग्य है।

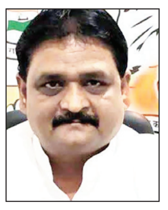

धान खरीदी की तारीख 15 दिन बढ़ाए सरकार : वर्मा

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने धान खरीदी की तिथि 15 दिन बढ़ाए जाने की मांग करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ में लगभग 3 लाख पंजीकृत किसान अपना धान नहीं बेच पाए हैं। अब तक की धान खरीदी सरकार के द्वारा ही निर्धारित लक्ष्य से लगभग 15 लाख मैट्रिक टन कम की हुई है। टोकन और बारदानों की कमी, परिवहन के अभाव में संग्रहण केंद्रों में बफर लिमिट से अधिक धान के जाम हो जाने के कारण धान खरीदी का कार्य बेहद धीमी गति से हुआ, जिसके चलते प्रदेश के लाखों किसान अपना धान नहीं बेच पाए हैं। सरकार धान खरीदी की तिथि 15 दिन बढ़ाये। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि सरकार की अपेक्षा, उदासीनता और बदइंतजामी के चलते ही छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार किसान अपने उपज को बेचने के लिए इतना परेशान हुआ। बारदाना की व्यवस्था से लेकर टोकन को लेकर पूरा सिस्टम लगातार बाधित होते रहा। मिलिंग और समय पर परिवहन करवाने में यह घोर लापरवाही बरती गई, पूर्ववर्ती सरकार में 72 घंटे के भीतर धान संग्रहण केंद्रों से धान के उठाव का जो नियम था उसे भी साय सरकार ने दुर्भावना पूर्वक बदल दिया। भाजपा सरकार की अकर्मण्यता के चलते ही प्रदेश के लाखों किसान अब तक अपना धान बेचने से वंचित रहे।

कृषि विश्वविद्यालय का दशम् दीक्षांत समारोह आज

रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर का दशम् दीक्षांत समारोह 1 फरवरी, 2025 को आयोजित किया जाएगा। कृषि महाविद्यालय रायपुर स्थित कृषि मंडपम में प्रातः 11 बजे से आयोजित इस दीक्षांत समारोह में लगभग 4 हजार 191 विद्यार्थियों को उपाधियाँ प्रदान की जाएगी। दीक्षांत समारोह राज्यपाल एवं इंदिरा गांधी कृषि विवि के कुलाधिपति रमेन डेका की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एण्ड बायोटेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के पूर्व निदेशक डॉ. वांगा शिवा रेड्डी दीक्षांत उद्बोधन देंगे। कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल विद्यार्थियों को दीक्षोपदेश देंगे। दीक्षांत समारोह के दौरान मेधावी विद्यार्थियों को 16 स्वर्ण, 18 रजत एवं 4 कांस्य पदक प्रदान किये जाएंगे। इस दौरान भव्य दीक्षांत शोभायात्रा भी निकाली जाएगी। दीक्षांत समारोह आयोजन स्थल कृषि मंडपम् तक दीक्षांत समारोह के पल-प्रतिपल कार्यक्रम के अनुसार रिहर्सल की गई, जिसमें विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव, अधिष्ठातागण, संचालकगण एवं गोल्ड, सिल्वर एवं ब्रोंज मेडल पाने वाले विद्यार्थी शामिल हुए। इस दौरान विश्वविद्यालय के कुलगीत, राज्यगीत तथा राष्ट्रगान का वादन किया गया। दीक्षांत समारोह में शैक्षणिक वर्ष 2022-23 एवं 2023-2024 तक कृषि विश्वविद्यालय के उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को पदक एवं उपाधियाँ वितरित की जाएँगी।

केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य का हिस्सा बढ़ाया जाए : गुप्ता

रायपुर। आज पेश होने वाले केंद्रीय बजट पर अपनी अपेक्षाएं व्यक्त करते हुए एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स इंडिया (एएचपीआई) छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता एवं महासचिव डॉ अतुल सिंघानिया ने कहा कि केंद्रीय बजट में कुल जीडीपी का 2 प्रतिशत हिस्सा स्वास्थ्य पर खर्च होना चाहिए यह अंतरराष्ट्रीय मानक के करीब है और कई उन्नतिशील देश अपनी स्वास्थ्य व्यवस्थओं पर इससे अधिक खर्च करते हैं। भारत में पिछले कई सालों में स्वास्थ्य पर खर्च जीडीपी का 1 फीसदी से कुछ अधिक है। देश की लगभग 40 प्रतिशत जनसंख्या को आयुष्मान योजना की लाभार्थी बनाने के लक्ष्यों को स्वास्थ्य का पर्याप्त बजट नहीं होने की वजह से नहीं पाया जा सका है। कम और अनियमित बजट प्रावधानों के चलते अस्पतालों को आयुष्मान योजना के ईलाज का समय पर भुगतान नहीं हो पा रहा है। अस्पतालों के बढ़ते संचालन व्यय की वजह से आयुष्मान योजना के पैकेज दरों के भी पुनर्निर्धारण किये जाने की जरूरत है। हाल के वर्षों में लाइफ स्टाइल बीमारियों या नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के मरीज बढ़ रहे हैं। इसके लिए प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव हेल्थ के बजट को बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।

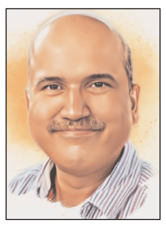

मुख्यमंत्री ने जवानों को दी बधाई

नक्सलवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है: सीएम

बस्तर में जल्द ही अमन, चैन और शांति का माहौल स्थापित होगा

रायपुर। हमारी नीति स्पष्ट है - बोली का जवाब बोली से और गोली का जवाब गोली से। जो भी नक्सली आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं, उनके लिए हमारी सरकार द्वारा बेहतर जीवन और पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जो हिंसा का रास्ता छोड़ गणतंत्र का मार्ग अपनाते हैं, उनका स्वागत है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बस्तर संभाग के अलग-अलग जिलों में लगातार नक्सलियों द्वारा किये जा रहे आत्मसमर्पण पर सुरक्षाबल के जवानों को बधाई देते हुए, उनके अदम्य साहस को नमन करते हुए कहा कि - आज कांकेर जिले में 7 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिन पर कुल 32 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इससे पहले नारायणपुर जिले के 27 एवं सुकमा जिले के 52 लाख के ईनामी 9 नक्सलियों ने सुरक्षाबलों के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। यह हमारी सरकार की प्रभावी आत्मसमर्पण नीति और नक्सलवाद के सफाए के लिए लगातार चलाए जा रहे अभियानों का प्रत्यक्ष परिणाम है।

सीएम साय ने कहा कि अब तक 941 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जबकि 1,112 नक्सलियों को हमारे सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया है। नक्सली मुठभेड़ों में 265 नक्सलियों का खात्मा हुआ है। नक्सलवाद की खोखली विचारधारा से त्रस्त होकर और बेहतर जीवन की उम्मीद में नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। यह इस बात का संकेत है कि नक्सलवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि मैं अपने बस्तर दौरे के दौरान अक्सर आत्मसमर्पित नक्सलियों से मिलता हूं। उनसे बातचीत में यह साफ झलकता है कि खोखली माओवादी विचारधारा को छोड़कर वे आज बेहतर जीवन जी रहे हैं और खुश हैं। घोर नक्सल प्रभावित जिलों के चिन्हित ग्रामों में नक्सल आधार को खत्म करने के लिए शासकीय योजनाओं के माध्यम से बुनियादी ढांचे और मूलभूत आवश्यकताओं का विकास कर रही है।

विष्णु देव साय ने कहा कि आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए 15 हजार प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं। तय समय-सीमा के भीतर माओवाद के आतंक का अंत होगा। बस्तर में जल्द ही अमन, चैन और शांति का माहौल स्थापित होगा।

ट्रांसमिशन कंपनी के कर्मियों को उत्कृष्टता सम्मान

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी ने क्षेत्रीय स्तर पर उत्कृष्ट कार्यों के लिये 10 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुरस्कृत किया। डंगनिया मुख्यालय स्थित सेवाभवन में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध निदेशक आरके शुक्ला ने कर्मियों को एक हजार रूपए नगद, प्रमाण पत्र एवं पदक देकर सम्मानित किया।

ट्रांसमिशन कंपनी की सु लिलेश्वरी वैष्णव (कार्यालय सहायक श्रेणी- एक, अति. उच्चदाब नि. एवं सं., बिलासपुर), सुखराम (लाइन सहायक श्रेणी-दो, टी.एल.एम, उपसंभाग, बिलासपुर), हर्षदीप वारे (सहायक अभियंता, मीटर रिले परीक्षण संभाग, रायगढ़), महेश कुमार चंद्रा (लाइन परिचारक संविदा, 132 केवी उपकेंद्र, कोरबा पूर्व), बसंत कुमार देवांगन (परिचारक श्रेणी-1, लाइन, बेल्टमैन, 220 केवी उपकेंद्र, भाटापारा), प्रेमचंद वर्मा (परिचारक श्रेणी-एक, लाइन, कार्यपालन अभियंता, कर्मशाला, भिलाई), सु नमिता विभा लकरा (कार्यपालन अभियंता, भार प्रेषण केंद्र, रायपुर), मती भारती पिल्लै (कार्यालय सहायक श्रेणी-2, मानव संसाधन, रायपुर), पंकज देवांगन (डाटा एंट्री ऑपरेटर, मानव संसाधन, रायपुर), जितेंद्र कुमार वर्मा (कार्यालय सहायक श्रेणी-2, लाइन, रायपुर) को उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन अतिरिक्त महाप्रबंधक (जनसंपर्क) उमेश कुमार मिश्र ने किया एवं आभार प्रदर्शन मुख्य अभियंता (मानव संसाधन) वीरेंद्र कुमार दीक्षित ने किया। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशकगण सर्व केएस मनोठिया, एमएस चौहान, संजय पटेल, आरसी अग्रवाल, जी आनंद राव विशेष रूप से उपस्थित थे।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.